www.ghoonghatkibagawat | www.ghoonghatkibagawat | ghoonghatkibagawat37@gmail.com

घूँघट की बगावत

UP/HIN/1999/1282

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित

हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

वर्ष : 24 अंक : 31 | गोरखपुर, 16 फरवरी 2025 रविवार | पृष्ठ : 6 | मूल्य : 2

▶ भारत पर अमेरिका का दूसरा बड़ा एक्शन

मोदी से मीटिंग के बाद भी नहीं माने ट्रंप?

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान ने अमेरिका से टेकऑफ ही किया था। इधर पीछे पीछे अमेरिका ने अपना एक और मिलिट्री विमान भारत भेज दिया है। पहले 104 अवैध भारतीयों की वापसी अमेरिका ने कराई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत लौटने के साथ ही अमेरिका ने अमेरिका ने अवैध प्रवासियों का दूसरा जत्था भी भारत भेजने का फैसला कर लिया है। इस बार खबर है कि अमेरिका से 119 अवैध भारतीय आ रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की गैरकानूनी अप्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई अब और पुख्ता और तेज हो चुकी है। महज कुछ ही दिनों के भीतर अब एक और जत्था भारत लौट रहा है। इस जत्थे में 119 अवैध भारतीयों को शामिल किया गया है। ये 119 अवैध भारतीय ठीक उसी तरह भारत लौटेंगे जैसे पहले लौटे थे। पैरों में जंजीर और हाथों में हथकड़ी बांधे ये अवैध भारतीय भारत लौट रहे हैं। बड़ी बात ये है कि इस बार भी अमेरिका ने इनकी वापसी के लिए मिलिट्री विमान का इस्तेमाल किया है। इस बार भी सी-17 विमान से ये अवैध भारतीय पंजाब के अमृतसर में लैंड करेंगे। सी-17 अमेरिकी सैन्य विमान पंजाब से 67, हरियाणा से 33, गुजरात से 8, उत्तर प्रदेश से 3, राजस्थान और महाराष्ट्र से 2-2 और गोवा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से 1-1 व्यक्ति को लेकर अपने साथ आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जब तक सभी अवैध प्रवासियों को उनके गृह देश वापस नहीं भेज दिया जाता तब तक ये कार्रवाई ऐसे ही जारी रहने वाली है। गैर कानूनी अप्रवासियों के लिए अमेरिका ने अपनी कार्रवाई और तेज कर दी है। दूसरी उड़ान शनिवार रात 10 बजे से 11 बजे के बीच अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने की उम्मीद है। पहली उड़ान में अधिकांश निर्वासित लोगों ने अमेरिका में प्रवेश करने के लिए अवैध डंकी मार्ग अपनाया था। कई लोगों ने बेईमान एजेंटों को भारी रकम चुकाने के बाद महीनों तक चलने वाली यात्राएं कीं। वापसी के बाद से पंजाब और हरियाणा सरकार ने ऐसे कई एजेंटों को गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अवैध आव्रजन के मुद्दे पर चर्चा हुई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि वे छात्रों और पेशेवरों की कानूनी गतिशीलता के लिए रास्ते को सुव्यवस्थित करने और अल्पकालिक पर्यटक और व्यावसायिक यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, साथ ही अवैध आव्रजन और मानव तस्करी को आक्रामक तरीके से संबोधित करने और निपटने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। दोनों पक्षों की ओर से उन तत्वों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता है जो सार्वजनिक और राजनयिक सुरक्षा के साथ-साथ दोनों देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को खतरा पहुंचाते हैं।

इस संबंध में कानून प्रवर्तन को मजबूत करने की प्रतिबद्धता है, जो कि घटित कुछ घटनाओं को देखते हुए हमारे दृष्टिकोण से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

गैस रिसाव : स्कूल में अफरातफरी, अचेत हुए 12 छात्र, अस्पताल में भर्ती

कोटा । राजस्थान के कोटा के सिमलिया थाना क्षेत्र में शनिवार को सीएफसीएल फैक्ट्री से अमोनिया गैस के रिसाव से कई छात्र बीमार पड़ गए। रिसाव से गढ़ेपान गांव के सरकारी स्कूल के छात्र प्रभावित हुए हैं। बच्चों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से छह की हालत गंभीर थी। न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक, आशुतोष शर्मा ने बताया ति जिन छात्रों को यहां रेफर किया गया था, उनकी हालत स्थिर थी। हमने उनका प्राथमिक उपचार किया और जेके लोन अस्पताल में रेफर किया। किसी की भी हालत गंभीर नहीं थी।

बताया जा रहा है कि गैस रिसाव से कुल 12 छात्र प्रभावित हुए हैं। उनमें से पांच को शुरू में कोटा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था, लेकिन उनकी बिगड़ती हालत के कारण बाद में उन्हें कोटा के जेके लोन अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल) फैक्ट्री में सुबह करीब 11 बजे गैस रिसाव हुआ। हाई सेकेंडरी स्कूल में छात्रों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। कुछ ही देर में उनमें से कुछ बेहोश हो गए, जिससे स्कूल में दहशत फैल गई। अराजकता फैल गई और अधिकारियों को तुरंत सूचित किया गया।

सीएफसीएल एक फैक्ट्री है जो यूरिया खाद का उत्पादन करती है। अधिकतम जानकारी के अनुसार, प्रभावित छात्रों का पहले फैक्ट्री परिसर में संचालित अस्पताल में इलाज किया गया। यह भी पता चला कि कुछ छात्राएं स्कूल परिसर में पानी लेने गई थीं, तभी उन्हें घुटन और बेचैनी महसूस होने लगी। उनकी हालत बिगड़ गई और उन्होंने स्कूल स्टाफ को सांस लेने में दिक्कत के बारे में बताया। खबर मिलने पर कोटा जिला कलेक्टर रवींद्र गोस्वामी घटनास्थल पर पहुंचे और फैक्ट्री और उपखंड प्रशासन से जानकारी जुटाई।

चकित्सा की वर्तमान चुनौतियों और उनके समाधान पर छात्र-छात्राओं से खुलकर की चर्चा

ग्रेटर नोएडा । आज दिनांक 15 फरवरी 2025 को जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान के 10वें स्थापना दिवस के मौके पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जहां एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे बच्चों से जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने सीधा संवाद करते हुए कहा कि ₹आप चिकित्सा को व्यवसाय नहीं वर-जनसेवा का माध्यम बनाएं।₹ जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने चिकित्सा की वर्तमान चुनौतियों और उनके समाधान पर भी छात्र-छात्राओं से खुलकर चर्चा की।

जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने इस मौके पर उपस्थित समस्त स्टाफ और बच्चों को संबोधित करते हुए आगे कहा कि चिकित्सा एक कला और सेवा करने का माध्यम है। इसे हमें धन कमाने का साधन नहीं बनना चाहिए। इस चिकित्सा पद्धति को मात्र व्यावसायिक दृष्टिकोण से न देखा जाए, बल्कि इसे जानता की सेवा के रूप में अपनाएं।₹ राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान के 10वें स्थापना दिवस के मौके पर जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने बताया कि ₹विगत 10 वर्षों में जिम्स एक ऐसा संस्थान बनकर उभरा है, जहां गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपना इलाज कर सकता है।

छात्र-छात्राओं से संवाद के दौरान जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने सन 1946 में डॉ. कोटनीस के ऊपर बनी फिल्म का भी उल्लेख करते हुए कहा कि ₹यह फि ल्म एक वास्तविक जीवन के डॉ. द्वारकानाथ कोटनीस के जीवन पर आधारित है, जो द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी आक्रमण के दौरान चीन में काम करने वाले एक भारतीय डॉक्टर थे और उन्होंने अपने मरीजों का इलाज करते हुए अपनी जान दे दी थी। इसलिए मुझे नजर आया कि ऊपर तो ईश्वर है और लोग नीचे डॉक्टर को भी इसी नजरिए से देखते हैं।

जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने अंत में कहा कि डॉक्टर्स के प्रति लोगों के जहन में जो धारणा और सम्मान है, उस धारणा और सम्मान में कमी नहीं आनी चाहिए।₹ स्थापना दिवस के मौके पर राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर श्री राकेश कुमार गुप्ता ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में इस अस्पताल में मरीजों की संख्या में पांच प्रतिशत की वृद्धि हुई है। साथ ही ऑपरेशन की संख्या में भी इजाफा हुआ है। मेरा दिल और दिमाग हमेशा मरीजों की सेवा में लगा रहता है।

वर्तमान में राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान में तकरीबन 400 डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। इस अस्पताल में लगभग 650 बेड मौजूद हैं। रोजाना तकरीबन 1000 से भी अधिक मरीज की जांच इत्यादि होती है। सीटी स्कैन, एमआरआई, विशिष्ट लैब तथा डायलिसिस की जांच बहुत कम पैसों में की जाती है। राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा सुविधा आदि लाभार्थियों के इलाज निशुल्क किए जाते हैं। ई संजीवनी सुविधा भी मरीज के हेतु संचालित की जा रही है। वर्ष 2019 से 100 एमबीबीएस की सीटों पर पाठ्यक्रम किया जा रहा है।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से संस्थान के डायरेक्टर राकेश कुमार गुप्ता, डीन डॉक्टर रंभा पाठक, डॉ रंजना वर्मा, डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव, डॉ मनीष सिंह, डॉक्टर नीतू भदोरिया, डॉक्टर शिवानी कलहान, डॉ जेएस तोमर आदि अनेकों डॉक्टर भी मौजूद रहे।

अमेरिका से अवैध प्रवासियों को बेड़ियों में जकड़ कर भेजना क्रूर और शर्मनाक: उमा भारती

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने अवैध भारतीय प्रवासियों को क्रूर एवं बेहद शर्मनाक तरीके से वापस भेजने के लिए शनिवार को अमेरिका की निंदा की।

अमेरिका का एक सैन्य विमान भारत के विभिन्न राज्यों के 104 अवैध प्रवासियों को लेकर पांच फरवरी को अमृतसर पहुंचा था।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत इन लोगों को भारत निर्वासित किया था।

कुछ निर्वासितों ने दावा किया कि पूरी यात्रा के दौरान उनके हाथ-पैरों में हथकड़ी लगी रही तथा अमृतसर में उतरने के बाद ही उनकी बेड़ियां खोली गईं।

भारती ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने पोस्ट में कहा,ह्यह्यअमेरिका से वापस भेजे गए अवैध प्रवासी भारतीयों को जिस तरह से हथकड़ियों एवं बेड़ियों में जकड़कर वापस भेजा गया, वह बेहद शर्मनाक एवं मानवता के लिए कलंक है।

उन्होंने कहा कि अमेरिकी सरकारों ने रेड इंडियंस और वहां रहने वाले अफ्रीकी मूल के लोगों के प्रति कई बार यह क्रूर और हिंसक रवैया दिखाया है। रेड इंडियन शब्द का इस्तेमाल यूरोपीय उपनिवेशवादियों द्वारा उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों के लिए किया जाता था।

भाजपा नेता ने कहा, जब उन्हें (निर्वासित लोगों को) विमान से भेजा जा रहा था तब उन्हें हथकड़ियों और बेड़ियों में रखना अमेरिकी प्रशासन की क्रूरता और अमानवीयता को दशार्ता है।

किसी देश में अवैध रूप से प्रवेश करना अपराध है, हर देश के कानून के अनुसार इसकी सजा का प्रावधान है, लेकिन ऐसी क्रूरता महा पाप है।

अमेरिका से 119 अवैध प्रवासियों को लेकर एक विमान शनिवार रात अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरेगा।

▶ फडणवीस ने त्रिवेणी संगम में लगाई आस्था की डुबकी

▶ 'भारतीय कूटनीति के लिए एक परीक्षा', डिपोर्टेशन पर चिदंबरम का सवाल

क्या निर्वासितों को हथकड़ी लगाई जाएगी?

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने शनिवार को कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय निर्वासित लोगों को लेकर दूसरे अमेरिकी विमान का आगमन भारतीय कूटनीति के लिए एक परीक्षण होगा। चिदम्बरम ने एक्स पर लिखा कि सभी की निगाहें अमेरिकी विमान पर होंगी जो आज अवैध अप्रवासियों को वापस लेकर अमृतसर में उतरेगा। क्या निर्वासितों को हथकड़ी लगाई जाएगी और उनके पैर रस्सियों से बांध दिए जाएंगे? उन्होंने आगे कहा, यह भारतीय कूटनीति के लिए एक परीक्षा है।

संयुक्त राज्य अमेरिका से 119 भारतीय निर्वासित लोगों को लेकर एक विमान शनिवार को अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरेगा। फ्लाइट के रात 10 बजे से 11 बजे के बीच एयरपोर्ट पर उतरने की उम्मीद है। 119 निर्वासितों में से 67 पंजाब से, 33 हरियाणा से, आठ गुजरात से, तीन उत्तर प्रदेश से, दो-दो गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान से और एक-एक हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर से हैं। भारत पहुंचने वाले निर्वासित लोगों में वे लोग शामिल हैं जो मेक्सिको और अन्य

मार्गों से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश कर चुके हैं।

अधिकारियों के अनुसार, उन्होंने अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने के तुरंत बाद कथित तौर पर अपने पासपोर्ट भी फाड़ दिए। डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन द्वारा अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने वाले लोगों पर अभूतपूर्व कार्रवाई के बीच अमृतसर के लिए उड़ानें वापसी करने वाले लोगों की दूसरी खेप हैं। इससे पहले, भारतीय निर्वासित लोगों को लेकर अमेरिकी वायु सेना का एक विमान 5 फरवरी को अमृतसर पहुंचा था। अमृतसर में उतरने वाले विमान में कुल 104 भारतीय नागरिक सवार थे।

'लव जिहाद' के खिलाफ कानून जल्द, सात सदस्यीय कमेटी गठित

पुणे । महाराष्ट्र सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के मामलों के खिलाफ संभावित कानून के लिए कानूनी ढांचे की जांच करने के लिए सात सदस्यीय समिति का गठन किया है। राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) संजय वर्मा की अध्यक्षता वाले पैनल में महिला एवं बाल कल्याण, अल्पसंख्यक मामले, कानून और न्यायपालिका, सामाजिक न्याय, विशेष सहायता और गृह जैसे प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। शुक्रवार देर रात जारी एक सरकारी संकल्प (जीआर) के अनुसार, समिति जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद से संबंधित शिकायतों से निपटने के उपाय सुझाएगी। यह अन्य राज्यों में मौजूदा कानूनों की भी समीक्षा करेगा और कानूनी प्रावधानों की सिफारिश करेगा।

श्रद्धा वाकर मामले के बाद महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन द्वारा लव जिहाद का मुद्दा, मुस्लिम पुरुषों द्वारा हिंदू महिलाओं को प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन कराने के कथित मामले उठाए गए हैं। महाराष्ट्र की 27 वर्षीय महिला वॉकर की कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी और 2022 में उसके लिव-इन पार्टनर आफताब पूनावाला ने उसके

▶ समिति जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद से संबंधित शिकायतों से निपटने के उपाय सुझाएगी।

▶ भाजपा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन द्वारा लव जिहाद का मुद्दा, मुस्लिम पुरुषों द्वारा हिंदू महिलाओं को प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन कराने के कथित मामले उठाए गए

शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया था। समिति गठित करने के सरकार के फैसले की विपक्ष ने आलोचना की है, एनसीपी (शरद पवार) नेता सुप्रिया सुले ने कहा है कि शादी करना या प्यार करना एक व्यक्तिगत पसंद है। मैं सरकार से वास्तविक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का अनुरोध करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी अभी अमेरिका से लौटे हैं और अमेरिका ने नये टैरिफ लगा दिये हैं, जिसका असर हमारे देश पर पड़ेगा. सरकार को ऐसे मामलों पर ध्यान देना चाहिए और आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने बीजेपी की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार का पूरा ध्यान मुसलमानों को परेशान करने और सांप्रदायिकता फैलाने पर है. ₹वे लिव-इन रिलेशनशिप के लिए आजादी देना चाहते हैं, लेकिन अगर 18 साल से अधिक उम्र का कोई व्यक्ति अंतरधार्मिक विवाह करना चाहता है या धर्म परिवर्तन करना चाहता है, तो उन्हें इससे समस्या है। लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है।

जे.डी.वेंस के भाषण ने यूरोपीय सत्ता प्रतिष्ठानों को हिलाया

वास्तव में भारत पश्चिमी देशों के सूचना एकाधिकार के दुष्परिणाम का भुक्तभोगी रहा है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर कहते रहे हैं कि भारत और उसकी सरकार की छवि खराब करने के लिए सुनियोजित अभियान चलाया जाता है। जयशंकर ने कुछ वर्ष पूर्व इसी म्यूनिख सम्मेलन में कहा था कि यूरोपीय देश यह मानते हैं कि इस महाद्वीप की समस्या विश्वव्यापी है जबकि अन्य देशों की समस्याओं से उनका कोई लेना-देना नहीं है। यह स्थिति ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती।

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वायदे के अनुसार कार्यकाल के आरंभ में ही युद्ध समाप्त कराने तथा शांति वार्ता आयोजित करने के संबंध में ठोस पहल की। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से लंबी बातचीत की। ट्रंप का शांति फामूर्ला है यूक्रेन में तुरंत युद्ध विराम हो तथा बातचीत शुरू हो। रूस को भरोसा दिलाया जाए कि यूक्रेन को कभी पश्चिमी देश सैन्य संगठन नाटो एवं सदस्य नहीं बनाया जाएगा। वास्तव में कुछ वर्ष पहले यदि यह घोषणा की गई होती तो युद्ध शुरू ही नहीं होता। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग सेथ ने नाटो की बैठक में अमेरिका के इसी रवैये को दोहराया जो यूरोपीय सदस्य देशों को नागवार गुजरा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की खुलकर ट्रंप प्रशासन का विरोध करने की स्थिति में नहीं हैं। हालांकि पर्दे के पीछे वह अमेरिका के खिलाफ यूरोपीय देशों की लामबंदी का प्रयास कर रहे हैं।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेड़ी वेंस का संबोधन यूरोप की सरकारों और नेताओं की नीतियों पर खुला प्रहार था। उन्होंने इन देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर अपनाई जा रही पाखंडपूर्ण नीतियों की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यूरोप को रूस और चीन सहित बाहरी शक्तियों के बजाय घरेलू ताकतों से असल खतरा है। जेडी वेंस ने आरोप लगाया कि यूरोपीय देशों में अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने की कोशिश की जा रही है जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्तोरियस ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। वास्तव में आव्रजन, इस्लामी कट्टरवाद, गर्भपात,पर्यावरण और वैक्सीन आदि मुद्दों पर ट्रंप प्रशासन तथा यूरोपीय नेताओं में मतभेद है। पिछले चुनाव में अमेरिकी मतदाताओं ने डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ ट्रंप को भारी जनादेश दिया था। ट्रंप प्रशासन अब इन्हीं नीतियों को अन्य देशों में फैलाना चाहता है। उपराष्ट्रपति वेंस का संबोधन ऐसे समय सामने आया है जब जर्मनी में आम चुनाव होने वाले हैं।

चांसलर शोल्ज को कड़ी चुनौती का सामना है। यूरोप की अन्य देशों की तरह जर्मनी में भी आव्रजन और इस्लामी कट्टरवाद विरोधी राजनीतिक दलों की ताकत बढ़ रही है। जर्मनी के दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी दल एडीएफ की ताकत में इजाफा हो रहा है। मस्क एड़ीएफ का समर्थन कर रहे हैं। जर्मनी और यूरोप के अन्य देशों में यह धारणा बन रही है कि ट्रंप प्रशासन चुनाव में दखलअंदाजी कर रहा है।

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद राजनीतिक और कूटनीतिक झटके यूरोप में महसूस किए जा रहे हैं। जर्मनी के शहर म्यूनिख में चल रहे सुरक्षा सम्मेलन में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के भाषण ने यूरोप के सत्ता प्रतिष्ठानों को हिला दिया है। कुछ महीने पहले तक अमेरिका यूरोप के नेता एक ही सुर में बोलते थे। यूक्रेन युद्ध सहित अनेक विश्व मामलों में दुनिया को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के बजाय आग में घी डालने का काम किया। यूक्रेन- रूस और यूरोप को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी।

यह विडंबना है कि कुछ दिन पहले जो यूरोपीय देश अन्य देशों को अभिव्यक्ति की आजादी की नसीहत दे रहे थे,वे आज खुद कठघरे में खड़े हैं। वास्तव में पश्चिम का वर्चस्ववादी वैश्विक तंत्र सूचना युद्ध पर टिका था।

सूचना के सभी माध्यमों पर इन देशों का एकाधिकार था। किसी भी मुद्दे पर घरेलू और विदेशी मोर्चे पर जनमत का निर्माण करने के लिए इस सूचना तंत्र का इस्तेमाल किया जाता था। ट्वीटर, फेसबुक और व्हाट्सएप आदि के प्रचलन के बाद लोगों को सूचना के वैकल्पिक माध्यम हासिल हुए।

एलन मस्क ने ट्वीटर का स्वामित्व हासिल करने के बाद इसे आंतरिक सेंसरशिप से मुक्त किया। वास्तव में भारत पश्चिमी देशों के सूचना एकाधिकार के दुष्परिणाम का भुक्तभोगी रहा है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर कहते रहे हैं कि भारत और उसकी सरकार की छवि खराब करने के लिए सुनियोजित अभियान चलाया जाता है। जयशंकर ने कुछ वर्ष पूर्व इसी म्यूनिख सम्मेलन में कहा था कि यूरोपीय देश यह मानते हैं कि इस महाद्वीप की समस्या विश्वव्यापी है जबकि अन्य देशों की समस्याओं से उनका कोई लेना-देना नहीं है। यह स्थिति ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने प्रकारांतर से जयशंकर के तर्क को ही आगे बढ़ाया है।

सोल्लासपूर्ण वातावरण में लला मेमे की मनी14वीं पुण्यतिथि

भुंतर/केलांग। लाहौल के आध्यात्मिक संत लला मेमे की शनिवार को 14वीं पुण्यतिथि भुंतर में मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत बैजनाथ के शर्बलिंग मठ के खेनपो पेमा नेगी और बदाह मठ के लामा नवांग ने 108 दीये जलाकर की। इस आयोजन में 500 से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लिया। शनिवार सुबह 07:00 बजे अमृत वाणी और फिर सोनम राम की ओर से शिव पूजन किया गया। इसमें उपस्थित श्रद्धालुओं ने पूर्णाहुति दी।

फाउंडेशन के अध्यक्ष मंगल मनेपा ने बताया कि दोनों संस्थाएं पश्चिमी हिमालय में कैंसर के प्रति जागरूकता लाएंगी। इस कार्य के लिए प्रोजेक्ट कॉज की अध्यक्ष सुरजीत चटर्जी और राजीव गांधी कैंसर अस्पताल दिल्ली से डॉ. सुमित गोयल लला मेमे की पुण्यतिथि में आए थे। पुण्यतिथि में बौध धर्मगुरु पेमा नेगी का प्रवचन हुआ। इसमें उन्होंने महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार किया और उपस्थित लोगों को सभागार में ध्यान लगाने की प्रक्रिया का अभ्यास करवाया। कार्यक्रम में लाहौल-स्पीति के चार लोगों को सम्मानित किया गया। इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। इनमें ठाकुर देवी सिंह, ठाकुर शिव चंद, पंडित बसंत राम और मुंशी सजे राम के परिवारों ने आकर स्मृति चिह्न लिए।

कड़ी मेहनत से आगे बढ़ता है व्यक्ति : मोहित

बरियाल (कांगड़ा)। बासा पंचायत के मोहित सिंह ने एचएएस मुख्य परीक्षा में प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। उनकी सफलता पर रामेश्वर मॉडल स्कूल बासा में सम्मान समारोह आयोजित हुआ। सम्मान समारोह में एचएएस अधिकारी मोहित सिंह ने अपनी उपलब्धि का श्रेय माता-पिता और शिक्षकों को दिया। मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य हरभजन सिंह सोहल की उपस्थिति में स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। मोहित ने विद्यार्थियों को सफलता के टिप्स देते हुए कहा कि कड़ी मेहनत से ही लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार को अपनी प्राथमिकता बताया और युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की।

धारकंडी में सड़कों के निर्माण पर खर्च होंगे 35 करोड़ : पठानिया

शाहपुर (कांगड़ा)। विधानसभा क्षेत्र शाहपुर के धारकंडी क्षेत्र में सड़क सुविधाओं के विकास के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा 35 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। उपमुख्य सचेतक केवल पठानिया ने घेरा-सुखुघाट-चमियारा-भितलु सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ करते हुए यह बात कही। 3.41 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस सड़क से 15 गांवों के हजारों लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि घेरा-बरनेट सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है। क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए करेरी के आसपास पांच नए स्थानों को इको-टूरिज्म के तहत चिह्नित किया गया है। मिडल स्कूल करेरी में दो नए कमरों का निर्माण शीघ्र कराया जाएगा। उन्होंने नौरा गांव को सड़क से जोड़ने के लिए सर्वे करने के भी आदेश दिए। उन्होंने खड़ीबही-रावा में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा 5 लाख रुपये की लागत से बने झूला पुल का लोकार्पण किया और करेरी में 20 लाख रुपये की लागत से बनने वाले वन खंड अधिकारी कार्यालय एवं आवास भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान, ग्रामीण विकास विभाग रैत के कार्यक्रम में जय शनिदेव, जय इंद्रुनाग, धौलाधार, गड़ेश्वरी और राधा कृष्ण महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई। उपमुख्य सचेतक केवल पठानिया और अधिकारियों ने वेलेंटाइन डे पर परांदे व अन्य उत्पाद भी खरीदे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विभिन्न स्थानों पर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर निपटारा किया गया और शेष को संबंधित विभागों को त्वरित समाधान के लिए भेजा गया।

आर्च ब्रिज और मनसा देवी मंदिर के सौंदर्यीकरण का भेजा प्रस्ताव

ऋषिकेश । प्रशासन 2027 में हरिद्वार में होने वाले अर्द्धकुंभ की तैयारियों में जुट गया है। कुंभ क्षेत्र के मंदिरों व पुलों के सौंदर्यीकरण की योजनाएं तैयार की जा रही है। देवप्रयाग संगम स्थल पर बने आर्च पुल और हरिद्वार के मनसा मंदिर को फसाड लाइट से सजाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।

ऋषिकेश शहर, आसपास के क्षेत्र और पुलों को फसाड लाइट से सजाने के बाद अब अर्द्धकुंभ क्षेत्र के अन्य शहरों में भी पुलों व मंदिरों को फसाड लाइट से सजाने की योजनाएं तैयार की जा रही हैं। जिसके तहत प्रथम चरण में देवप्रयाग संगम स्थल पर बने आर्च पुल और हरिद्वार के मनसादेवी मंदिर को फसाड लाइट से सजाने की योजना है। इसके लिए विद्युत यांत्रिकी खंड लोनिवि ऋषिकेश ने शासन को प्रस्ताव बना कर भेजा है।

पुल और मंदिर को फसाड लाइट से सजाने के लिए डेढ़-डेढ़ करोड़ का प्रस्ताव बना कर भेजा गया है। देवप्रयाग संगम आर्च ब्रिज पर फसाड लाइट से देवी-देवताओं के चित्र भी उकेरे जाएंगे। जबकि मंशा देवी मंदिर को सिर्फ फसाड लाइट से सजाया जाएगा।

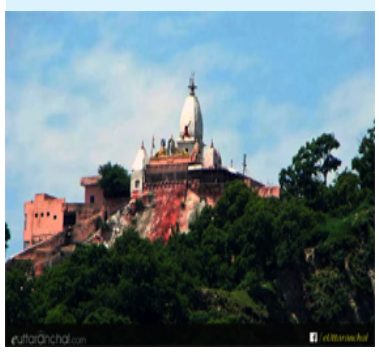

घृत गुफा से बाहर निकले जागेश्वर महादेव

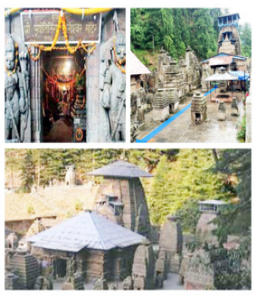

जागेश्वर (अल्मोड़ा)। एक माह बाद माघ पूर्णिमा पर गत बुधवार को श्रद्धालुओं को जागेश्वर महादेव के वास्तविक स्वरूप में दर्शन हुए। भोलेनाथ बुधवार को घृत गुफा से बाहर निकाले गए। इसके बाद पुजारियों ने उनका रूद्राभिषेक कर आरती उतारी, फिर घी का प्रसाद वितरित किया। स्मरणीय है कि 4 जनवरी को भोलेनाथ एक माह के लिए घृत गुफा में विराजमान हो जाते हैं। बुधवार सुबह मंदिर में पुजारियों ने नियमित पूजा-अर्चना की। इसके उपरांत माघ पूर्णिमा के पावन दिवस पर मंत्रोच्चारण के बीच पंडित तारा दत्त भट्ट सहित अन्य पुजारियों ने जागेश्वर महादेव को घृत गुफा से बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद सभी पुजारियों ने भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया और आरती उतारी। इसके बाद सभी लोगों को घी का प्रसाद दिया गया। इस पूजा में पुजारी हरीश भट्ट, लक्ष्मी दत्त भट्ट, हिमांशु भट्ट, लोकेश भट्ट, त्रिलोचन भट्ट, केवल भट्ट, भगवान भट्ट, मोहन भट्ट आदि शामिल हुए। भनोली के एसडीएम एनएस नगन्याल व पुजारी प्रतिनिधि नवीन चंद्र भट्ट व तारा भट्ट ने भगवान जागेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया।

इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा यह शतक:रेखा आर्या

देहरादून । राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड की टीम ने पदकों की सेंचुरी मारकर इतिहास रच दिया। खेल मंत्री रेखा आर्या ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रदेश के सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा, पदकों की संख्या के मामले में अब तक उत्तराखंड का सर्वाधिक स्कोर गोवा में 24 पदक का रहा। अपने पुराने बेस्ट को चार गुना से भी ज्यादा के अंतर से तोड़ना अपने आप में हमारे खिलाड़ियों की मेहनत और समर्पण की कहानी को बताता है।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि नौ नवंबर 2023 को जैसे ही उत्तराखंड को 38वें नेशनल गेम्स की मेजबानी की औपचारिक रूप से जिम्मेदारी मिली, उसके बाद से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने खिलाड़ियों के पक्ष में उन बड़े फैसलों से माहौल को बदलना शुरू किया, जिनका नतीजा आज देखने को मिल रहा है। खेल मंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, पदक जीतने पर नौकरी, सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, पदक विजेताओं को दोगुनी इनाम राशि, खेल विश्वविद्यालय और महिला स्पोर्ट्स कॉलेज जैसी योजनाओं ने देवभूमि को खेल भूमि बनने की तरफ अग्रसर कर दिया है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा, प्रदेश के गांव से जो खेल प्रतिभाएं निखरकर इन राष्ट्रीय खेलों में आगे आई है अब हम उन्हें एशियाड और ओलंपिक में चैंपियन बनने के लिए तैयार करेंगे।

उत्तराखंड में खुशी की लहर...

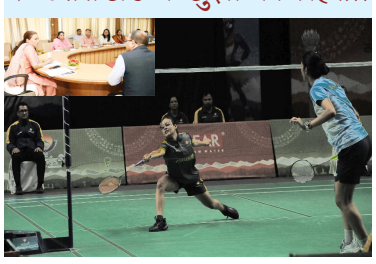

खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा, इन राष्ट्रीय खेलों में जीते गए पदकों की संख्या के मामले में उत्तराखंड चौथे नंबर पर पहुंच गया है। जनसंख्या की दृष्टि से देश में 21 वां स्थान रखने वाला राज्य अगर पदकों की संख्या के मामले में चौथे नंबर पर है तो इसके लिए सभी प्रदेशवासियों को हमारे खिलाड़ियों की प्रतिभा और मेहनत पर गौरव होना चाहिए।

नेटबॉल के फाइनल मैच में जैसे ही उत्तराखंड की टीम ने बृहस्पतिवार शाम देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में सिल्वर मेडल जीता, इसके साथ ही उत्तराखंड की मेडल की सेंचुरी पूरी हो गई।

खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्यमिता विकास केंद्र की शुरूआत

मौलेखाल (अल्मोड़ा)। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान अनुसंधान (यूसर्क) के सहयोग से सल्ट ब्लॉक के हिनौला में बुधवार को श्रम योग व रचनात्मक महिला मंच के केंद्र पर खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्यमिता विकास केंद्र की शुरूआत हो गई जो लंबे प्रयासों के बाद संभव हो सका है। अब यह केंद्र क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं की आजीविका वृद्धि का जरिया बनेगा।

श्रमयोग व रचनात्मक महिला मंच क्षेत्र में कई सालों से महिला हितों तथा उनकी आजीविका के लिए काम करती है। इस मंच से सल्ट ब्लॉक की करीब 1200 महिलाएं जुड़ी हैं और आय अर्जन करती हैं। बुधवार को हिनौला में यह केंद्र अस्तित्व में आ गया।

मौके पर मंच की अध्यक्ष सुनीता देवी ने कहा कि श्रमयोग के लंबे प्रयासों के बाद यूसर्क के सहयोग से केंद्र मिल पाया है। मंच की संरक्षक निर्मला देवी ने यूसर्क का आभार जताते हुए कहा कि इस केंद्र से महिलाओं की आमदनी में इजाफा होगा। श्रमयोग के शंकर दत्त ने कहा कि अब अपने केंद्र पर महिलाएं अपने कृषि उत्पादों को बेच सकेंगे और उन्हें बेहतर दाम मिलेंगे। श्रमयोग के अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार ने कहा कि केंद्र की स्थापना से मंच मजबूत होगा।

बौखनाग देवता की डोली ने किया कुंड की जातर का शुभारंभ

बड़कोट। गंगनानी में तीन दिवसीय वसंतोत्सव मेले (कुंड की जातर) का शुभारंभ क्षेत्र के आराध्य बौखनाग देवता की डोली के सानिध्य में पूर्व विधायक केदार सिंह रावत और प्रशासक जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण ने किया। इस दौरान मेला मंच पर कलाकारों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों कि प्रस्तुति दी।

मेले के शुभारंभ पर बतौर मुख्यतिथि यमुनोत्री के पूर्व विधायक केदार सिंह रावत ने कहा कि यह मेला सदियों से चला आ रहा है। मेले से हमारी पौराणिक काल से धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्वता जुड़ी हुई है। कहा कि गंगा यमुना और केदार गंगा इस त्रिवेणी संगम पर क्षेत्र के लोगों की शादियां होती रहती हैं। इसके लिए उन्होंने यहां अपने कार्यकाल में सामूहिक बहुद्देश्यीय बारात घर का निर्माण किया। वहीं मेला आयोजक प्रशासक जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण ने कहा कि मेले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे।

घूँघट की बगावत

16 फरवरी 2025

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

साकार होगा खोराबार टाउनशिप के नये गोरखपुर में बसने का सपना: योगी

गोरखपुर (जीकेबी)। खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी परियोजना में बसने का पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों का सपना साकार होगा। उक्त बातें खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी परियोजना में 91.56 करोड़ रुपए से गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 6.63 एकड़ में १४ मंजिला टावर के मिनी एलआईजी के सैंपल फ्लैट का निरीक्षणोपरान्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहीं।

प्राधिकरण उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताया कि यहां पर 420 मिनी एमआईजी फ्लैट निमार्णाधीन हैं। प्रत्येक फ्लैट की कीमत तकरीबन 28.58 लाख रुपए होगी। ब्लाक एक में स्टिल्ट समेत 12 मंजिल तक निर्माण हो चुका है। जबकि ब्लाक दो में स्टिल्ट का काम पूरा हो चुका है। इसके पूर्व उपाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी परियोजना की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने सीएम को जानकारी दी कि खोराबार में अर्जित 187 १८७ एकड़ भूमि लैण्ड मोनिटाइजेशन पद्धति (भूमि मौद्रीकरण) पर 245 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत पर 598 आवासीय, ग्रुप हाउसिंग के 08, व्यावसायिक के 35, स्कूल-क्लब के दो और मेडिसिटी के अन्तर्गत हास्पिटल,नर्सिगहोम के 83 भूखण्ड, स्पेशल इन्स्टीटयूट और धर्मशाला के चार भूखण्डों समेत कुल 728 भूखण्ड होंगे। परियोजना यूपी रेरा में पंजीकृत है। भूखण्डों का आवंटन ईझलाटरी के माध्यम से किया जा रहा है। विकास कायाड्ड को समय से पूर्ण करने के लिए विकासकर्ता से सौ करोड की बैंक गारण्टी ली गई है। मुख्यमंत्री को यह भी जानकारी दी गई कि ईडब्लूएस श्रेणी के 560, एलआईजी श्रेणी के 480, मिनी एमआईजी श्रेणी के 420 और एमआईजी श्रेणी के 560 भवनों का निर्माण माईवन तकनीक से हो रहा है। ढाई साल में निर्माण कार्य पूरे हो जाएंगे।

पीएमएलए का दहेज कानून की तरह हो रहा दुरुपयोग:उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने एक आरोपी को जेल में रखने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) का इस्तेमाल करने के लिए ईड़ी की आलोचना की और सवाल किया कि क्या दहेज निषेध कानून की तरह इस प्रावधान का भी 'दुरुपयोग' किया जा रहा है। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने बुधवार को छत्तीसगढरूके पूर्व आबकारी अधिकारी अरूण पति त्रिपाठी को जमानत देते हुए यह टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि अगर शिकायत पर संज्ञान लेने वाले अदालती आदेश को छत्तीसगढरूउच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था, तो आरोपी को हिरासत में कैसे रखा गया।

पीठ ने पूछा 'व्यक्ति को जेल में रखना पीएमएलए की अवधारणा नहीं हो सकती। अगर संज्ञान रद्द होने के बाद भी व्यक्ति को जेल में रखने की प्रवृत्ति है, तो क्या ही कहा जा सकता है? देखें कि 498 ए मामलों में क्या हुआ था, पीएमएलए का भी उसी तरह दुरुपयोग किया जा रहा है भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए विवाहित महिलाओं को पतियों और उनके रिश्तेदारों की क्रूरता से बचाती है।

सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईड़ी) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जमानत देने का विरोध करते हुए कहा कि तकनीकी आधार पर अपराधी बच नहीं सकते। राजू ने कहा कि मंजूरी के अभाव में संज्ञान रद्द कर दिया गया था और यह जमानत के लिए अप्रासंगिक है। पीठ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा यह चौंकाने वाला है कि ईड़ी को पता है कि संज्ञान रद्द कर दिया गया था फिर भी इसे दबा दिया गया। हमें अधिकारियों को तलब करना चाहिए। ईड़ी को साफझसाफ बताना चाहिए।

शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा 'हम क्या दिखाना चाह रहे हैं? संज्ञान लेने का आदेश रद्द किया जा चुका है फिर भी व्यक्ति हिरासत में है। शीर्ष अदालत भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारी त्रिपाठी की अपील पर सुनवाई कर रही थीड्डजिसमें उन्होंने राज्य में चर्चित आबकारी घोटाले के सिलसिले में जमानत देने से इनकार करने वाले छत्तीसगढरूउच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। प्रतिनियुक्ति पर छत्तीसगढरू राज्य विपणन निगम लिमिटेड़ के विशेष सचिव और प्रबंध निदेशक रहे त्रिपाठी को ईड़ी ने जांच के बाद गिरफ्तार किया था।

अपनी मांगों के समर्थन में भाकपा किसान सभा का धरना, तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

आजमगढ़। बिजली के निजीकरण, किसानों और जनसमस्याओं सहित पांच सूत्री मांगों को लेकर रेडहा बिजली सब स्टेशन के सामने अखिल भारतीय किसान सभा ने धरना दिया। इस बीच धरना स्थल पर पहुंचे तहसीलदार को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा।

धरने को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज बेग ने कहा कि सरकार उद्योगपतियों के हाथों की कठपुतली बन गई है। किसानों के मुद्दे पर सरकार मौन हो जाती है, नहरों में पानी नहीं है, गन्ना की पर्ची नहीं मिल रही है। किसानों को उत्पादन का लागत मूल्य नहीं मिल रहा। विकास के नाम पर बजट का बंदरबांट हुआ। बिजली विभाग दंबई कर रही है। मनमाने ढंग से कमजोर तपके से बिल वसूल रहा है। कनेक्शन काट कर जोड़ने के नाम पर अवैध वसूली कर रहा है। थाना, ब्लॉक, तहसील में भ्रष्टाचार व्याप्त है। जिलाध्यक्ष त्रिलोकीनाथ ने कहा कि अहरौला-कप्तानगंज मार्ग को तत्काल जनहित में बनाया जाए। यदि जल्द मांग पूरी नहीं हुई तो वृहद आंदोलन करेंगे।

आयुष्मान कार्ड वितरित

मेरठ। सामान्य वर्ग के लिए केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना के अंतर्गत 70 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष और महिलाओं के आयुष्मान कार्ड वितरण दिगंबर जैन महा समिति के तत्वाधान में आयोजित आयुष्मान कार्ड शिविर में बनाए गए। कार्ड के लाभार्थियों को गत शुक्रवार को डीएम वीके सिंह द्वारा आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया। इस योजना के लाभार्थियों में पदमचंद जैन, सितारा जैन, जनेश्वर जैन, वीरेंद्र कुमार जैन आदि लगभग 10 महिलाओं व पुरुषों के इस आयुष्मान कार्ड बने हैं, जिनको डीएम ने अपने कार्यालय में बुलाकर वितरण किया है। इस वितरण समारोह में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अशोक कटारिया, सह मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आरके सरोहा, डॉ. अर्चिता सिंह, जिला केमिस्ट एसोसिएशन के महामंत्री रजनीश कौशल, दिगंबर जैन महासमिति उत्तर प्रदेश अध्यक्ष विनेश कुमार जैन, पारस जैन, पुनीत जैन आदि उपस्थित रहे। बताया गया कि इस समिति द्वारा लगभग डेढ़ सौ कार्ड बनवाए गए थे और सरकार द्वारा निर्धारित मेरठ जिले में एक लाख के लक्ष्य को प्राप्त करने में इस शिविर की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी।

आवश्यकता से अधिक चीनी कर रही लीवर को फैटी

गोरखपुर। शराब की तरह चीनी भी लिवर को खराब कर रही है। अधिक चीनी लोगों को बीमार कर रही है। जरूरत से अधिक चीनी लीवर को फैटी लीवर बना रही है। शराब नहीं पीने वाले (नान अल्कोहलिक) फैटी लिवर के मरीजों की बढ़रूती संख्या की सबसे बड़ी वजह चीनी बन रही है। शरीर में पहुंच रही जरूरत से अधिक चीनी लिवर के आसपास फैट के रूप में जमा होकर बीमारी बढ़रू रही है। रोजाना 25 ग्राम से अधिक चीनी का उपयोग करना सेहत से खिलवाड़.करना साबित हो सकता है।

ज्ञानवर्धक सूत्र शराब पीने वाले 13 प्रतिशत लोग ही फैटी लीवर के शिकार हैं। चीनी के सेवन से दांत खराब हो सकते हैं। ब्लड शुगर स्पाइक हो सकता है। पर, अब यह भी सच है कि चीनी लिवर को डैमेज भी

कर सकती है। चीनी लिवर को शराब की तरह नुकसान पहुंचाती है। चीनी की कम मात्रा भी लिवर के लिए फायदेमंद नहीं है। जिस तरह शराब की हर बूंद लिवर को डैमेज करती है और फैटी लिवर का कारण बनती है, उसी तरह चीनी भी फैटी लिवर के लिए जिम्मेदार है। चीनी एक तरह का कार्ब है। जब हम इसे खाते हैं तो शरीर को एनर्जी मिलती है। शरीर इसको ग्लूकोज में बदल कर उपयोग करती है। इससे खूब कैलोरी मिलती हैं, लेकिन इसमें कोई पोषण नहीं होता है। शरीर चीनी का कुछ हिस्सा ही एनर्जी के लिए इस्तेमाल करता है। बची हुई चीनी फैट के रूप में लिवर तथा शरीर के अन्य हिस्सों में जमा होने लगती है। लिवर के पास इसके जमा होने से फैटी लिवर बीमारी होती है। लिवर के कुल वजन का पांच प्रतिशत फैट भी एकत्र होने से लिवर की सेहत बिगड़ने लगती है। आमतौर पर फैटी लिवर का कोई लक्षण नजर नहीं आता है। कभीझकभी थकान महसूस हो सकती है या पेट के > पर की तरफ दाहिनी ओर दर्द भी महसूस हो सकता है। इसके अलावा आंखों और स्किन में पीलापन, पेट में दर्द, पेशाब का गाढक्ष रंग, पेट में सूजनड्ड काले रंग का स्टूल, स्किन में खुजली, सांस लेने में दिक्कत व पैरों में सूजन जैसे लक्षण दिख सकते हैं।

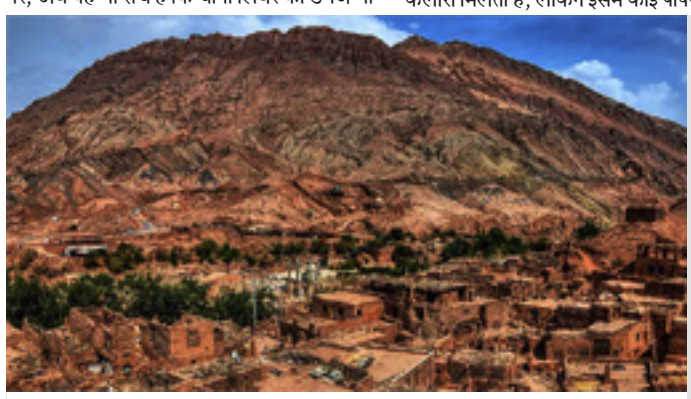

हमारे पड़ोसी देश चीन ने पिछले सप्ताह एक बार फिर से सुर्खियां बनाई। इस बार भारत में घुसपैठ नहीं बल्कि भारत और दुनिया भर के लिए एक उदाहरण बना। चीन ने अपने नवाचार द्वारा एक रेगिस्तान को न सिर्फ रोका बल्कि उसे हराझभरा भी कर दिया। चीन का यह विकास कार्य इन दिनों काफी चर्चा में है।

तकलामाकन रेगिस्तान का विकास कार्य :चीन की पर्यावरणीय संसाधनों के प्रति प्रतिबबद्धता दर्शाती

मौत का सागर' के रूप में जाने जाना वाला तकलामाकन रेगिस्तान 337-600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका आकार लगभग पश्चिमी देश जर्मनी के बराबर का क्षेत्र है। इसके विशाल रेत के टीलों और बार-बार आने वाले रेतीले तूफानों ने लंबे समय तक मौसम के पैटर्न को बाधित किया है। कृषि को खतरे में डाला है और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित किया है। जवाब में चीन ने एक व्यापक हरित अवरोध लागू किया है जिसे रेगिस्तान के किनारों को लॉक करने और इसके नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इन प्रयासों ने न केवल रेलवे और राजमार्गों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा की है, बल्कि यह भी प्रदर्शित किया है कि टिकाऊ प्रौद्योगिकियां मरुथलीकरण का प्रतिकार कैसे कर सकती हैं।

सौर ऊर्जा से संचालित सिंचाई प्रणालियों को एकीकृत करके, चीन पृथ्वी पर सबसे कठिन वातावरणों में से एक में वनस्पति को बनाए रखने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। तकलामाकन रेगिस्तान के इस व्यापक पहल पर चार दशकों से काम चलाया गया। ग्रीनबेल्ट का पहला 2761 किलोमीटर का काम कई वर्षों में पूरा हुआ, अंतिम चरण नवम्बर 2022में शुरू हुआ, जिसमें रेगिस्तानी चिनार,लालविलो और सैक्सौल पेड़ों जैसी लचीली, रेगिस्तान-अनुकूल प्रजातियों को रोपने के लिए 600,000 श्रमिकों को एक साथ लाया गया-जो शुष्क परिस्थितियों में जीवित रहने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। ये पौधे कई उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, वे खिसकती रेत को सहारा देते हैं, रेगिस्तान के विस्तार को धीमा करते हैं और स्थानीय समुदायों को आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं। यह परियोजना इतिहास में सबसे महत्वाकांक्षी पुनर्वनीकरण प्रयासों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है जो दुनिया भर में भूमि क्षरण से निपटने के लिए एक नई मिसाल कायम करती है। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में ग्रीनबेल्ट का प्राथमिक लक्ष्य मरुस्थलीकरण को रोकना है, यह परियोजना दीर्घकालिक आर्थिक अवसर भी पैदा कर रही है। कुछ नये लगाए गए पेड़ जैसे कि रेगिस्तानी जलकुंभी में औषधीय गुण होते हैं, जो संभावित रूप से हर्बल चिकित्सा के लिए आकर्षक बाजार खोलते हैं। इसके अलावा, 2022 में चीन ने हॉटन-रुओकियांग रेलवे का उद्घाटन किया,जो रेगिस्तान के चारों ओर दुनिया की पहली पूरी तरह से घिरी हुई रेलवे थी। 2,712 किलोमीटर लंबा रेलवे रेगिस्तानी शहरों को जोड़ता है जिससे अखरोट और लाल खजूर जैसे स्थानीय कृषि उत्पादों को पूरे चीन के बाजारों तक पहुंचाना आसान हो जाता है जिससे क्षेत्रीय व्यापार और विकास को और बढ़ावा मिलता है। ज्ञानवर्धक सूत्रानुसार, चीन पुनर्वनरोपण पर रोक नहीं लगा रहा है बल्कि तकलामाकन रेगिस्तान में एक विशाल नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना भी चल रही है। चाइना थ्री गोरजेस कॉर्पोरेशन 8.5 गीगावाट सौर ऊर्जा और 4 गीगावाट पवन ऊर्जा स्थापित करने की योजना का नेतृत्व कर रहा है, जिसके अगले चार वर्षों में पूरा होने की उम्मीद है। रेगिस्तान की बहाली को टिकाऊ ऊर्जा उत्पादन के साथ जोड़कर, चीन उस चीज को हरित विकास के अवसर में बदल रहा है जो कभी एक पारिस्थितिक चुनौती थी। गक्षैरतलब है कि तकलामाकन ग्रीनबेल्ट की सफलता मरु स्थलीकरण और भूमि क्षरण से निपटने के वैश्विक प्रयासों के अनुरूप है। इसी तरह की बड़े पैमाने की परियोजनाएं, जैसे कि अखेका की ग्रेट ग्रीन वॉल, का उद्देश्य पूरे महाद्वीप में आठ हजार किलोमीटर लंबे वृक्ष अवरोधक लगाकर सहारा रेगिस्तान के विस्तार को रोकना है। तकलामाकन रेगिस्तान का विकास कार्य समान पारिस्थितिक खतरों का सामना करने वाले अन्य देशों के लिए एक खाका के रूप में भी कार्य कर रहा है। यह उपलब्धि नवीन पर्यावरणीय समाधानों के प्रति चीन की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। हरित प्रौद्योगिकियों और बड़े पैमाने पर पुनर्वनीकरण का लाभ उठाकर, राष्ट्र ने न केवल अपने स्वयं के बुनियादी ढांचे और कृषि को सुरक्षित किया है, बल्कि भविष्य की वैश्विक रेगिस्तान बहाली परियोजनाओं के लिए भी मार्ग प्रशस्त किया है। भारत सहित सभी विकासशील देशों को चीन से सबक लेते हुए यह सीखना चाहिए कि विषम परिस्थितियों में भी विकास कार्य किए जा सकते हैं। ओछी राजनीति करने से किसी का भी लाभ नहीं होता। यदि केंद्र में और राज्य में दो अलग दलों की सरकार भी हो तो विकास कार्यों पर किसी भी तरह की रोक लगाना आम जनता के साथ धोखा है। इसलिए यदि सही सोच वाला नेतृत्व सही योजनाओं को स्वीकृति करे तो ऐसे भ्रष्टाचार से बचा जा सकता है और ताकलामाकन रेगिस्तान जैसे कई विकास कार्य दोहराया जा सकते हैं।

▶ इजहार ए मोहब्बत का दिवस वेलेंटाइन डे

पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंगा रहा महानगर

गोरखपुर। प्रेम का प्रतीक वेलेंटाइन डे यूं तो यह पश्चिमी सभ्यता का प्रतीक है लेकिन आज हर कोई इसके रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। शहर के युवाओं ने गत शुक्रवार को वेलेंटाइन्स डे.उत्साह पूर्वक मनाया। सुबह से लेकर देर शाम तक इजहार ए मोहब्बत का दौर चलता रहा। पार्क- रेस्टोरेंट पिकनिक स्पॉट पर युवाओं की भीड़ लगी रही। कुछ ने एक दूसरे को गिफ्ट दिए तो कुछ ने गुलाब के फूल देकर अपने प्रेम को प्रगाढ़ रूबनाया।

शहर के रामगढ़ताल लेक व्यू प्वाइंट एवं जेट्टी पर नव विवाहित जोड़े नजर आए। कई तो अपने वेलेनटाइन के साथ सेल्फी लेते दिखे। इसी प्रकार से व्ही पार्क, रेल म्यूजियम, अंबेड़कर पार्क, पंत पार्क आदि युवाओं के आकर्षण का केन्द्र बना रहा।

पार्क के साथ ही शहर के मॉल भी युवाओं से गुलजार रहा। ओरियन मॉल, एड़ी मॉल और सिटी मॉल में बड़ी संख्या में युवा अपने साथियों के साथ पहुंचे। ऐसे में मॉल वालों ने भी इनके लिए विशेष इंतजाम किए थे। वहीं रेस्त्रां और होटल में भी युवा अपने साथियों के साथ पहुंचकर इजहार ए मोहब्बत किया। युवाओं सहित कपल्स में भी काफी उत्साह देखने को मिला। बाजारों में इस मौके पर कोई अपने पति के लिए उपहार खरीदने में मशरुफ दिखा तो कोई अपने पार्टनर के साथ उपहार खरीदते दिखे। हर साल की तरह इस बार भी वेलेंटाइन डे पर फूलों की जमकर बिक्री हुई।

विदित हो कि इस दौरान कुछ युवाओं और कपल्स ने बताया कि वेलेंटाइन डे प्रेम का प्रतीक है इस दिन वह अपनों को तरह तरह के उपहार देकर उनको अपने प्यार का एहसास कराते हैं। तो वहीं युवाओं से हटकर कुछ अन्य लोगों से बात करने पर उन्होंने बताया कि प्यार के मायने को समझने की जरुरत है। प्रेम करना कोई गुनाह नहीं होता है। यह तो देवी देवताओं के समय से चलता आ रहा है।

जल्द ही शुरू होगी हवा बस सेवा : नीतिन गडकरी

लखनऊ। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को यहां इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि यूपी की राजधानी लखनऊ में जल्द हवा में चलने वाली बस सेवा का शुभारंभ होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध किया है कि मैं लखनऊ में हवा में चलने की शुरू आत करना चाहता हूं। इसके लिए आपसे पैसे नहीं चाहिए, मैं लखनऊ में हवा बस सेवा शुरू करवा दूंगा। लखनऊ में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ चार लेन की दो प्रमुख फ्लाईओवर का उद्घाटन के बाद अपने विचार व्यक्त कर रहे थे।

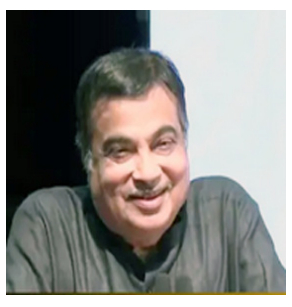

नितिन गडकरी ने कहा कि मैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से अनुरोध करता हूं कि दिल्ली में हवा बस का प्रेजेंटेशन देखने जरूर आएं। केंद्रीय मंत्री गड़करी ने इस दौरान कई घोषणाएं की और कहा कि भोपाल-कानपुर इकोनॉमिक कोरिडोर भी जल्द बनेगा। दिल्ली से देहरादून अब सिर्फ दो घंटे में जायेंगे। यूपी में 25 हजार करोड़ के 6 ग्रीन रिंग रोड को मंजूरी दी है।

उन्होंने कहा कि पूर्वांचल को औद्योगिक विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए वाराणसी से कोलकाता और गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक 75 हजार करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री एवं सांसद राजनाथ सिंह ने कहा कि लखनऊ में केवल सड़कों का ही विकास नहीं बल्कि हवाई सेवाओं को भी विस्तार देने के लिए लखनऊ एयरपोर्ट का विस्तार किया जा रहा है जिससे अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की सुविधा और बेहतर हो सके।

इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ में डिफेंस कॉरिडोर के तहत ब्रमोस मिसाइल निर्माण परियोजना का उद्घाटन आगामी मई-जून में किया जाएगा।

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कुल 588 करोड़ रुपए की 114 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया गया।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने इस मौके पर कहा कि डबल इंजन की सरकार लखनऊ को न केवल एयरो सिटी बल्कि कृत्रिम मेधा (एआई) शहर के रूप में भी विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि लखनऊ को एक हजार करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनायें मिली है, जिसमें440 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग की दो महत्वपूर्ण परियोजनाएं और करीब 600 करोड़ रुपए की विभिन्न राज्य परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास शामिल है।

घूँघट की बगावत

16 फरवरी 2025

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

4

कीर्ति ने कांग्रेस को दिखाया आईना

तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद ने इंडि गठबंधन और कांग्रेस पर जुबानी हमले किये हैं आजाद का यह कहना कि लोकल और विधानसभा चुनावों कांग्रेस अपने सहयोगियों का नुकसान करेगी । यह बात दक्षिण भारत में तर्कसंगत नहीं है। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को तो कांग्रेस ने ही नुकसान पहुंचाया और शिवसेना को भाजपा ने ही तोड़ा। पंजाब में अकाली दल की भी दुर्गति हुई। फिर, जिस दिल्ली के नतीजों की आड़ में आप की आलोचना की जा रही है, उस सन्दर्भ में यह याद दिलाया जाना काफी है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही आप ने ताबड़तोड़ अपने उम्मीदवार घोषित कर दिये थे जबकि कांग्रेस वहां तालमेल की इच्छुक थी। वह चाहती थी कि उसे करीब 15 सीटें दी जायें जो कि वाजिब मांग थी। अब कीर्ति का मानना है कि पश्चिम बंगाल राज्य में अकेली ममता या टीएमसी भाजपा से निपटने के लिये काफी है, कुछ वैसा ही गुमान आप को भी था। यह तो सही है कि पिछली दो बार की तरह इस बार भी कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली लेकिन आप ने कांग्रेस को साथ न लेकर सरकार गंवाई है ऐसा मानना है राजनीतिक विश्लेषकों का । यह अब साफ हो गया है कि भाजपा को रोकना कांग्रेस या किसी और के बस की बात नहीं। दिल्ली में कम से 15 सीटें ऐसी थीं जिन पर यदि दोनों मिलकर लड़ते तो वे सीटें गठबन्धन के खाते में आतीं । उससे नये सियासी समीकरणों के संकेत मिलते । यह अलग बात है कि उनके इन बयानों में विरोधाभास भी हैं। तो भी जो तल्खी टीएमसी सांसद ने दिखाई है, वह बतलाती है कि इंडिया से कुछ दल अलग हो सकते हैं और यह भी सम्भव है कि विपक्षी दल नये समीकरण रच सकते हैं।

राजनीतिक विश्लेषक एवं पत्रकार पंकज सीबी मिश्रा ने कीर्ति आजाद के बयानों को राजनीतिक स्टंट करार दिया और कहा कि कांग्रेस अब पश्चिम बंगाल में क्या उत्तर देती है, यह देखने वाली बात है तभी भावी घटनाओं का अनुमान लगाया जा सकता है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार का ठीकरा एक तरह से कांग्रेस पर फोड़ते हुए पूर्व क्रिकेटर तथा बर्धमान-दुर्गापुर के सांसद कीर्ति आजाद ने यह भी साफ किया कि- ह्य2026 में होने वाले राज्य के विधानसभा चुनाव में टीएमसी अकेली उतरेगी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का कोई आधार नहीं है इसलिये अपने हितों की अनदेखी कर टीएमसी गठबन्धन को मजबूत करने के फेर में नहीं पड़ेगी ह्ल वैसे भी टीएमसी अध्यक्ष तथा प. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस आशय का ऐलान सोमवार की पार्टी बैठक में कर ही दिया है। आजाद ने यहां तक कहा कि -ह्यकांग्रेस ने सहयोगी दल आप की पीठ में छुरा घोंपा है। उसे इंडिया में बने रहने का अधिकार नहीं है ह्ल वे पहले ही बोल चुके चुके हैं कि गठबन्धन का नेतृत्व करने के लिये ममता बनर्जी से बेहतर कोई भी नहीं है जिन्होंने अपने राज्य में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से हराया है। जहां तक महाराष्ट्र व हरियाणा का मसला है, यह नहीं भूलना चाहिये कि इन राज्यों में भाजपा ने अच्छा किया है । महाराष्ट्र में लोकसभा से विधानसभा चुनावों के बीच जिस प्रकार से 72 लाख मतदाता भाजपा की तरफ बढ़ गये, वह सबके ध्यान में है। हरियाणा में प्रारम्भ से आगे चल रही कांग्रेस को जिस तरह से कुछ मिनटों के भीतर अच्छी रणनीति और कटोगे तो बटोगे से निपटाया गया, उसे भी नजरंदाज नहीं किया जा सकता। गड़बड़ दिल्ली में हुई है जहां भाजपा ने अकेले फ्री वाला पैंतरा चल आप के गेम को बिगाड़ दिया लेकिन बहस ऐसी दिशा में मोड़ दी गयी है जैसे इसके लिए केवल राहुल जिम्मेदार है । स्वयं इंडिया के घटक दलों के द्वारा कांग्रेस पर हमला करके, कि यहां आम आदमी पार्टी के शराब की धांधली पर न किसी गठबंधन वाले नेता का ध्यान जा रहा है और न ही उसे कोई चर्चा में ला रहा है। स्वाभाविकतः यह स्थिति भाजपा, सरकार और दिल्ली वालों के पक्ष में बनती है कि उस पर आरोप लगाने का किसी के पास अब समय ही नहीं है। कीर्ति आजाद भूल जाते हैं कि ममता के इशारे पर पश्चिम बंगाल में धांधलियां हर स्तर पर होती है । उस राज्य में खूब होती है क्युकी अब बंगाल में अराजकता चरम पर है ऐसे में कांग्रेस कैसे हमलवार होगी यह देखना दिलचस्प है । बेशक, पश्चिम बंगाल में भी भाजपा अच्छा लड़ेगी । कीर्ति आजाद का यह बयान लगभग उसी लाइन पर है जिस पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम व शिवसेना (यूबीटी गुट) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे दे चुके हैं। एक तरह से महाराष्ट्र, हरियाणा और उसके बाद दिल्ली हारने के बाद कांग्रेस पर हमले तेज हो गये हैं जो बतलाते हैं कि कुछ दल कांग्रेस को लेकर बेचैन हैं। इन बातों में दम तो हैं लेकिन गठबन्धन यह भूल जाता है कि कांग्रेस केवल नेतृत्व नहीं कर रही है बल्कि उसके पास अपनी दलीय

कीर्ति आजाद का यह बयान लगभग उसी लाइन पर है जिस पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम व शिवसेना (यूबीटी गुट) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे दे चुके हैं। एक तरह से महाराष्ट्र, हरियाणा और उसके बाद दिल्ली हारने के बाद कांग्रेस पर हमले तेज हो गये हैं जो बतलाते हैं कि कुछ दल कांग्रेस को लेकर बेचैन हैं।

जरूरतें भी हैं जिनमें से एक है खुद को मजबूत बनाना तथा चुनाव लड़ना। इंडिया के शेष जितने भी घटक दल हैं उनकी मौजूदगी एक-एक राज्य में ही है, आप को छोड़कर जिसने अभी दिल्ली खोई है पर पंजाब में उसकी सरकार है। वैसे अनेक मुद्दों पर अकेले कांग्रेस ने आवाज उठाई लेकिन उससे पूरा इंडिया लाभान्वित हुआ है। फिर वह चाहे अंबानी-अदानी का मुद्दा हो या जातिगत जनगणना का।

पंकज सीबी मिश्रा
जौनपुर

'यू.एस. इंडिया कॉम्पैक्ट' चुनौतियाँ और अवसर

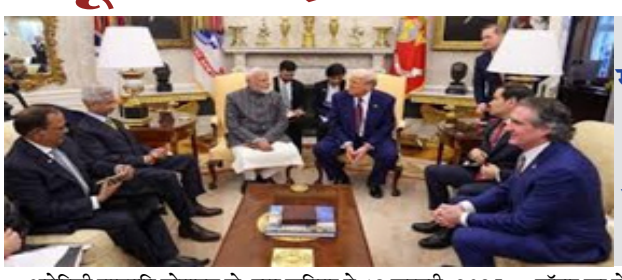

संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच बदलती गतिशीलता का इक्कीसवीं सदी में दुनिया के संगठित होने के तरीके पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इस साझेदारी की क्षमता को पूरी तरह से साकार करने के लिए, दोनों सरकारों को रणनीतिक बहुपक्षीय सम्बंधों, अर्थशास्त्र और रक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। मौजूदा हालात अमेरिका-भारत सम्बंधों के दीर्घकालिक विकास के पक्ष में हैं। मुझे उम्मीद है कि भारत चुनौतियों के साथ-साथ अवसरों को भी स्वीकार करने के लिए तैयार है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्प जूनियर ने 13 फरवरी, 2025 को वाशिंगटन डीसी में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आधिकारिक कार्य यात्रा के लिए स्वागत किया। राष्ट्रपति ट्रम्प और प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्र और गतिशील लोकतंत्रों के नेताओं के रूप में भारत-अमेरिका साझेदारी की ताकत की पुष्टि की, जो स्वतंत्रता, मानवाधिकार, कानून और बहुलवाद का सम्मान करते हैं। आपसी विश्वास, साझा हित, सद्भावना और सक्रिय नागरिक भागीदारी इस व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की नींव के रूप में काम करते हैं। राष्ट्रपति ट्रम्प और प्रधानमंत्री मोदी ने ₹यू.एस. इंडिया कॉम्पैक्ट₹ नामक एक बिल्कुल नया कार्यक्रम पेश किया, जिसका अर्थ है ₹सैन्य साझेदारी, त्वरित वाणिज्य और प्रौद्योगिकी के लिए अवसरों को उत्प्रेरित करना₹, जिसका उद्देश्य इक्कीस-वीं सदी में सहयोग के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्रांति लाना है। रणनीतिक और आर्थिक वातावरण लगातार अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों द्वारा नया रूप ले रहे हैं। कई क्षेत्रों में, भारत के बढ़ते नवाचार और अमेरिका की तकनीकी श्रेष्ठता एक दूसरे से मिलती है। भारत को $45 बिलियन के अधिशेष से लाभ होने के साथ, द्विपक्षीय व्यापार $118 बिलियन से ऊपर चला गया। प्रगतिशील आर्थिक सम्बंधों के माध्यम से, यह साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को नया रूप देती है, सुरक्षा में सुधार करती है और आपसी विकास को बढ़ावा देती है। अमेरिका और भारत के बीच व्यापार, रक्षा और प्रौद्योगिकी सभी में वृद्धि हुई है।

संचार संगतता और सुरक्षा समझौता और बेसिक एक्सचेंज ऐंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट जैसे महत्त्वपूर्ण समझौते, जो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और रक्षा रसद में घनिष्ठ सहयोग की गारंटी देते हैं, पर अमेरिका और भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। लक्षित सैन्य अभियानों के लिए भारत को अमेरिकी भू-स्थानिक खुफिया जानकारी तक पहुँच प्रदान करके, 2020 बेसिक एक्सचेंज ऐंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट समझौते ने हिंद महासागर क्षेत्र में स्थितिजन्य जागरूकता में सुधार किया। महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल जैसी पहलों ने सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी महत्त्वपूर्ण तकनीकों में सहयोग को मजबूत किया है। भारत और माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने 2.75 बिलियन डॉलर का सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने के लिए मिलकर काम किया, जो आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन को बढ़ाएगा। अमेरिकी हाइड्रोकार्बन के एक महत्त्वपूर्ण आयातक के रूप में, भारत हरित ऊर्जा स्रोतों पर स्विच करने में सहायता करता है। तेल आयात के मामले में, संयुक्त राज्य अमेरिका 2024 में 413.61 मिलियन डॉलर के साथ पांचवें स्थान पर रहा। लचीली आपूर्ति श्रृंखलाएँ, विशेष रूप से आवश्यक वस्तुओं के लिए, चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के दोनों देशों के प्रयासों का लक्ष्य हैं। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका क्वाड राष्ट्रों का हिस्सा हैं। अमेरिका और भारत के बीच व्यापार वार्ता में मुख्य बाधा टैरिफ विवाद है। भारत द्वारा अमेरिकी वस्तुओं, विशेष रूप से कृषि और तकनीकी क्षेत्रों पर उच्च टैरिफ लगाए जाने से व्यापार संतुलन प्रभावित होता है और वार्ता अक्सर बाधित होती है।

मादक पेय पदार्थों पर भारत द्वारा लगाए गए 150 प्रतिशत टैरिफ ने अमेरिकी निर्यातकों की बाजारों तक पहुँच को प्रतिबंधित करने के लिए अमेरिका की आलोचना की है। भारत में जेनेरिक दवा उद्योग सुलभ दवा की गारंटी के लिए अधिक संतुलित रणनीति का पक्षधर है, जबकि अमेरिका मजबूत बौद्धिक संपदा सुरक्षा चाहता है। बौद्धिक संपदा सुरक्षा के बारे में चिंताओं के कारण अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने भारत को अपनी ₹प्राथमिकता निगरानी सूची₹ में रखा। ई-कॉमर्स विनियमों और प्रस्तावित डेटा स्थानीयकरण कानूनों पर भारत की अलग-अलग स्थिति अमेरिकी हितों के विपरीत है। गूगल और अमेजन जैसे अमेरिकी निगमों द्वारा इस बारे में चिंता व्यक्त की गई थी कि भारत का व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक सीमा पार डेटा प्रवाह को कैसे सीमित करेगा। अमेरिका और भारत के बीच $45 बिलियन का व्यापार घाटा बाजार पहुँच बढ़ाने और टैरिफ कम करने के लिए अमेरिकी दबाव को प्रेरित करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने घुटने के प्रत्यारोपण और स्टेंट जैसे चिकित्सा उपकरणों पर कम टैरिफ का अनुरोध करके व्यापार असंतुलन को कम करने की मांग की। भारत के फाइटोसैनिटरी नियम जो अमेरिकी कृषि उत्पादों को प्रतिबंधित करते हैं, इस क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार के विस्तार में बाधा डालते हैं। चूंकि व्यापार वार्ता ने रक्त भोजन युक्त पशु आहार के मुद्दे को हल नहीं किया है, इसलिए भारत ने अमेरिकी डेयरी आयात को प्रतिबंधित कर दिया है।

एलएनजी और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग अमेरिका की एक प्रमुख उत्पादक के रूप में स्थिति और भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं के कारण संभव हुआ है। उदाहरण के लिए, इस तरह की साझेदारी भारत को ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस के अनुपात को मौजूदा 6 प्रतिशत से बढ़ाकर कुल प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण का 15 प्रतिशत करने के अपने लक्ष्य तक पहुँचने में मदद करेगी। लाभकारी शर्तों पर रक्षा हार्डवेयर का सह-उत्पादन रणनीतिक सम्बंधों को मजबूत करते हुए भारत की अन्य देशों पर निर्भरता को कम कर सकता है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत में लड़ाकू जेट इंजन के संयुक्त निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और अंतरिक्ष अन्वेषण जैसी महत्त्वपूर्ण तकनीकों में घनिष्ठ सम्बंधों द्वारा सहयोगी नवाचार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। सहकारी अंतरिक्ष अन्वेषण और चंद्र मिशन के लिए आर्टेमिस समझौते में भारत को भागीदार के रूप में स्वीकार किया गया था। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के भारत के प्रयास अमेरिका की ₹चीन+1₹ नीति के पूरक हैं, जो मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं में साझा उद्देश्यों को बढ़ावा देते हैं। उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के माध्यम से भारत में उत्पादन बढ़ाकर, एप्पल और सैमसंग ने चीनी कारखानों पर अपनी निर्भरता कम कर दी। एक ऐसा समझौता जो अधिक व्यापक है, उसे सीमित व्यापार समझौते द्वारा सुगम बनाया जा सकता है जो बाजार पहुँच में सुधार और टैरिफ विवादों को निपटाने पर केंद्रित है।

डॉ. सत्यवान सौरभ

भारत और अमेरिका ने कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने पर सहमति व्यक्त की, जो एक व्यापक समझौते की संभावना का संकेत देता है। व्यापार असंतुलन को हल करके विश्व स्थिरता की नींव एक मजबूत भारत-अमेरिका गठबंधन हो सकता है।

बढ़ते पारा में गेहूं उत्पादक चिंतित

हाल की रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि भारत को फरवरी 2025 में सामान्य से अधिक जनवरी के बाद औसत तापमान का अनुभव होने की उम्मीद है। यह असुविधाजनक गर्मी प्रमुख सर्दियों की फसलों जैसे गेहूं, रेपसीड और छोले के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है, जो अक्टूबर और दिसंबर के बीच लगाए जाते हैं और इष्टतम विकास के लिए शांत मौसम की आवश्यकता होती है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित गेहूं उगाने वाले प्रमुख राज्यों में उच्च तापमान और औसत से कम वर्षा के कारण पैदावार कम हो सकती है।

इन चुनौतियों के जवाब में, भारत सरकार ने किसानों को गेहूं की एकड़ का विस्तार करने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नए मौसम वाले गेहूं के लिए न्यूनतम खरीद मूल्य में 6.6% की वृद्धि की है। इसके अतिरिक्त, जलवायु-लचीला बीज किस्मों को विकसित करने के प्रयास चल रहे हैं जो चरम मौसम की स्थिति का बेहतर सामना कर सकते हैं।

हालांकि, बठिंडा, पंजाब के लिए वर्तमान मौसम पूर्वानुमान, अगले सप्ताह में 10 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान के साथ धुंधली स्थिति को इंगित करता है, जो इस अवधि के लिए सामान्य सीमा के भीतर है। हालांकि तत्काल चिंताओं को कम किया जा सकता है, बढ़ते तापमान की समग्र प्रवृत्ति क्षेत्र में गेहूं उत्पादकों के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बनी हुई है।

विजय गर्ग
मलोट पंजाब

बिखर रहे चूल्हे सभी, सिमटे आँगन रोज। नई सदी ये कर रही, जाने कैसी खोज॥

पिछले कुछ समय में पारिवारिक ढांचे में काफी बदलाव हुआ है। मगर परिवारों की नींव का इस तरह से कमजोर पड़ना कई चीजों पर निर्भर हो गया है। अत्यधिक महत्त्वाकांक्षी होना ही रिश्ते टूटने की प्रमुख वजह है। जब परिवारों में होड लगनी शुरू हो जाये एवं एक दूसरे के सुख-दुख से ज्यादा परस्पर प्रतिस्पर्धा का भाव जग जाये। समझना कि परिवार अथवा रिश्ते अपनी अंतिम सांस गिन रहे है। परिवार के टूटने के कारण अचानक पैदा नहीं होते। कई बार और समस्याएँ भी हो सकती है जैसे पैसा, प्रॉपर्टी, पसंद-नापसंद आदि। छोटे-मोटे झगड़े, किसी सदस्य की अनदेखी वगैराह के चलते भी अक्सर परिवारों में मनमुटाव हो जाता है। पर जो भी हो परिवार सबसे बडे सर्पोट सिस्टम में से एक होता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए की परिवार की मूल अवधारणा ज़िंदा बनी रहे और केवल मर्दस डे, फार्दस डे या सोशल मीडिया तक सीमित होकर न रह जाए।

आज सभी को एक संस्था के रूप में पारिवारिक मूल्यों और परिवार के बारे में सोचने-समझने की बेहद सख्त जरूरत है और साथ ही इन मूल्यों की गिरावट के कारण ढूँढकर उनको दुरुस्त करने की भी जरूरत है। इसके लिए समाज के कर्णधार कवि / लेखकों / गायकों / नायक / नायिकाओं / शिक्षक वर्गों और अन्य सामाजिक कार्यकताओं के साथ-साथ राजनीतिज्ञों को एक संस्था के रूप में परिवार के पतन के निहितार्थ के बारे में भी लिखना और सोचना चाहिए। खुले मंचो से इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि इस गिरावट के कारण क्या है? और इस गिरावट से कैसे उभरा जा सकता है? युवा कवि डॉ सत्यवान सौरभ ने इस स्थिति को अपने शब्दों में कहते हुए सही लिखा है कि-

'टूट रहे परिवार हैं, बदल रहे मनभाव।
प्रेम जताते गैर से, अपनों से अलगाव॥
बिखर रहे चूल्हे सभी, सिमटे आँगन रोज।
नई सदी ये कर रही, सौरभ कैसी खोज॥'

परिवार, भारतीय समाज में, अपने आप में एक संस्था है और प्राचीन काल से ही भारत की सामूहिक संस्कृति का एक विशिष्ट प्रतीक है। नैतिक मजबूती के साथ-साथ यह व्यक्ति के परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों को बिना किसी हिचकिचाहट के कठिन समय में भरोसा करने के लिए लचीलापन प्रदान करता है। यह कठिनाइयों से निपटने के लिए अनैतिक साधनों के उपयोग से बचाता है। परिवार लोगों को सांसारिक समस्याओं के प्रति स्त्री के दृष्टिकोण को विकसित करने में मदद करता है। मगर वर्तमान दौर में हम संस्था के रूप में परिवार में गिरावट का कटु अनुभव झेल रहे है।

' घर-घर में मनभेद है, बचा नहीं अब प्यार॥
फूट-कलह ने खींच दी, हर आँगन दीवार॥
स्नेह और आशीष में, बैठ गई है रार।
अरमानों के बाग में, भरा जलन का खार॥'

गिरावट के प्रतीक के रूप में आज परिवार खंडित हो रहा है, वैवाहिक सम्बन्ध टूटने, आपसे भाईचारे में दुश्मनी एवं हर तरह के रिश्तों में कानूनी और सामाजिक झगड़ों में वृद्धि हुई है। आज सामूहिकता पर व्यक्तिवाद हावी हो गया है। वर्तमान स्थिति में भड़काऊ रवैया परिवारों के बिखरने का प्रमुख कारण है। परिवार के अन्य सदस्यों को उच्च आय और कम जिम्मेदारी ने विस्तारित परिवारों को विभाजित किया है। आज के अधिकांश सामाजिक कार्य, जैसे कि बच्चे की परवरिश, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, बुजुर्गों की देखभाल आदि; बाहर की एजेंसियों, जैसे क्रेच, मीडिया, नर्सरी स्कूलों, अस्पतालों, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों, धर्मशाला संस्थानों ने ठेकेदारों के तौर पर संभाल लिए हैं जो कभी परिवार के बड़े लोगों की जिम्मेवारी होती थी।

'बड़े बात करते नहीं, छोटों को अधिकार।
चरण छोड़ घुटने छुए, कैसे ये संस्कार॥
कहाँ प्रेम की डोर अब, कहाँ मिलन का सार।
परिजन ही दुश्मन हुए, छुप-छुप करे प्रहार॥'

परिवार संस्था के पतन ने हमारे भावनात्मक रिश्तों में बाधा पैदा कर दी है। एक परिवार में एकीकरण बंधन आपसी स्नेह और रक्त से सम्बंध हैं।

एक परिवार एक बंद इकाई है जो हमें भावनात्मक सम्बंधों के कारण जोड़कर रखता है। नैतिक पतन परिवार के टूटने में अहम कारक है क्योंकि वे बच्चों को दूसरों के लिए आत्म सम्मान और सम्मान की भावना नहीं भर पाते हैं। पद-पैसों की अंधी दौड़ से आज सामाजिक-आर्थिक सहयोग और सहायता का सफाया हो गया है। परिवार अपने सदस्यों, विशेष रूप से शिशुओं और बच्चों के विकास और विकास के लिए आवश्यक वित्तीय और भौतिक सहायता तक सिमित हो गए हैं, हम आये दिन कहीं न कहीं बुजुर्गों सहित अन्य आश्रितों की देखभाल के लिए, अक्षम और दुर्बल परिवार प्रणाली की गिरावट की बातें सुनते और देखते हैं जब उन्हें अत्यधिक देखभाल और प्यार की आवश्यकता होती है।

भविष्य में संस्था के रूप में परिवार में गिरावट समाज में संरचनात्मक परिवर्तन लाएगी। सकारात्मक पक्ष पर, भारतीय समाज में जनसंख्या की वृद्धि में कमी देखी जा सकती है और संस्था के रूप में परिवार में गिरावट के प्रभाव के रूप में हो सकता है। हालाँकि, संयुक्त परिवार से परिवार के संरचनात्मक परिवर्तनों को समझने की आवश्यकता है, कुछ मामलों में इसे परिवार प्रणाली की गिरावट नहीं कहा जा सकता है। जहाँ परिवार प्रणाली किसी सकारात्मक परिवर्तन के लिए संयुक्त परिवार से एकल परिवार में परिवर्तित होती है। वैसे भी भारतीय समाज भी परिवार के संलयन और विखंडन की अनूठी विशेषता का निवास करता है जिसमें भले ही परिवार के कुछ सदस्य अलग-अलग स्थानों में अलग-अलग रहते हैं, फिर भी एक परिवार के रूप में रहते हैं।

' बच पाए परिवार तब, रहता है समभाव।
दुःख में सारे साथ हो, सुख में सबसे चाव॥
अगर करें कोई तीसरा, सौरभ जब भी वार॥
साथ रहें परिवार के, छोड़े सब तकरार॥'

परिवार एक बहुत ही तरल सामाजिक संस्था है और निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया में है। आधुनिकता समान-लिंग वाले जोड़ों (एलजीबीटी सम्बंध), सहवास या लिव-इन सम्बंधों, एकल-माता-पिता के घरों, अकेले रहने वाले या अपने बच्चों के साथ तलाक का एक बड़ा हिस्सा उभरने का गवाह बन रहा है। इस तरह के परिवारों को पारंपरिक रिश्तेदारी समूह के रूप में कार्य करना आवश्यक नहीं है और ये सामाजीकरण के लिए अच्छी संस्था साबित नहीं हो सकती। भौतिकवादी युग में एक-दूसरे की सुख-सुविधाओं की प्रतिस्पर्धा ने मन के रिश्तों को झुलसा दिया है।

कच्चे से पक्के होते घरों की ऊँची दीवारों ने आपसी वातालाप को लुप्त कर दिया है। पत्थर होते हर आंगन में फूट-कलह का नंगा नाच हो रहा है। आपसी मतभेदों ने गहरे मन भेद कर दिए है। बड़े-बुजुर्गों की अच्छी शिक्षाओं के अभाव में घरों में छोटे रिश्तों को ताक पर रखकर निर्णय लेने लगे है। फलस्वरूप आज परिजन ही अपनों को काटने पर तुले है। एक तरफ सुख में पडोसी हलवा चाट रहें है तो दुःख अकेले भोगने पड़ रहें है। हमें ये सोचना-समझना होगा कि अगर हम सार्थक जीवन जीना चाहते है तो हमें परिवार की महत्ता समझनी होगी और आपसी तकरारों को छोड़कर परिवार के साथ खड़ा होना होगा तभी हम बच पायंगे और ये समाज रहने लायक होगा।

प्रियंका सौरभ

आम जन की आय बढ़ाकर खर्चा बढ़ाया जाएगा

हमारी अर्थव्यवस्था खपत आधारित है, इसलिए बजट में आमजन की आय को बढक्षकर खर्च को बढ़ावा देने की पहल की गई है और इस क्रम में पर्यटन, आधारभूत संरचना और शहरी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि बुनियादी सुविधाएं बेहतर हों। साथ ही बड़ी संख्या में देश में रोजगार के अवसर पैदा हों और लोग आत्मनिर्भर बनकर अपनी सभी जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकें।

आज पर्यटन क्षेत्र की विकास दर लगभग दस प्रतिशत के आसपास है और इस रफ्तार को और भी तेज करने के लिए देश के शीर्ष 50 पर्यटन स्थल को विकसित किया जाएगा और बौद्ध धर्म से जुड़े धार्मिक स्थलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस क्रम में होम स्टे को बढ़ावा देने के लिए पात्र लोगों को मुद्रा लोन दिया जाएगा। इससे महंगे पर्यटन स्थल पर आम पर्यटकों को सस्ती दर पर रहने की सुविधा मिल सकेगी। इन स्थलों पर आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए जमीन राज्य सरकारें उपलब्ध कराएंगी और वहां पर उपलब्ध होटलों को हार्मोनाइज्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर मास्टर सूची में शामिल किया जाएगा, जिससे उन्हें वित्तीय सहायता और विकास संबंधी सुविधाएं मिल सकेगी। इन उपायों से स्थानीय अर्थव्यवस्था और भी मजबूत होगी और पर्यटकों का यात्रा अनुभव बेहतर हो सकेगा। पर्यटन स्थल का बेहतर प्रबंधन और प्रदर्शन करने वाले राज्यों को प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस क्रम में 50 प्रतिशत लागत बांड, बैंक ऋण और पीपीपी मॉडल यानी सार्वजनिक-निजी भागीदारी से वित्तपोषित होगी। इसके लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए दस हजार करोड़ रुपए का आवंटन भी किया जाएगा। अर्बन चैलेंज फंड की मदद से शहरों को स्मार्ट बनाया जाएगा। अर्थात इस फंड का उपयोग शहरों की आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने में किया जाएगा। देश में शहरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है साथ ही साथ हमारी आबादी भी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए, शहरों की आधारभूत संरचना को बढ़ती आबादी के अनुरूप विकसित करने की जरूरत है क्योंकि यह उस अनुपात में नहीं बढ़ रहा है जिससे परिवहन, गृह निर्माण, कचरा प्रबंधन जैसी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने बजट में बुनियादी ढांचा के विकास और नवाचार पर जोर दिया है। इसके तहत राज्यों को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 50 वर्षों तक के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 1.5 लाख करोड़ रुपए मुहैया कराएगी। इसके अतिरिक्त आगामी पांच वर्षों में नई परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना के जरिये नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए दस लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य पीपीपी मॉडल के जरिये प्रस्ताव तैयार कर इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड के तहत केंद्र से मदद पा सकेंगे। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मेक इन इंडिया की पहल को अभी और भी आगे बढाया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की जाएगी जो राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों के लिए नीतिगत समर्थन, प्रशासन और निगरानी ढांचा उपलब्ध कराएगा। इसका उद्देश्य कारोबार को सुगम बनाना, मांग वाली नौकरियों के लिए कार्यबल तैयार करना, एमएसएमई क्षेत्र की गतिशीलता को बढ़ाना, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों का उत्पादन आदि सुनिश्चित करना है। एमएसएमई वर्गीकरण के लिए निवेश और कारोबार की सीमाओं को क्रमशः 2.5 गुना और 2.0 गुना तक बढ़ाने को भारतीय उत्पादों का विनिर्माण बढ़ाने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। इससे देश के निर्यात को गति मिल सकती है। अभी यह क्षेत्र 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार के साथ विनिर्माण में 36 प्रतिशत का योगदान देता है। देश की अर्थव्यवस्था के खपत आधारित होने के कारण बजट में बचत और निवेश पर विशेष जोर दिया गया है। आज शहरों को स्मार्ट बनाने के साथ-साथ वहां सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराना बेहद आवश्यक है। जब शहर स्मार्ट एवं गंदगी रहित होंगे साथ ही सभी सुविधाओं से परिपूर्ण होंगे तभी वहां रोजगार सृजन होगा लोग बीमार नहीं पड़ेंगे, जिससे उस राशि का इस्तेमाल विकास से जुड़े कार्यों में किया जा सकेगा। जाहिर है पर्यटन और शहरी क्षेत्र के विकास से बचत और निवेश में तेजी आएगी और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी बुद्ध सर्किट विकसित किए जाने से उत्तर प्रदेश के सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, बिहार के राजगीर, बोधगया, वैशाली,मध्य प्रदेश के सांची, महाराष्ट्र के अमरावती, तेलंगाना के नागार्जुनकोंडा आदि आकर्षक पर्यटन स्थलों में तब्दील होंगे, जिससे पर्यटन आधारित उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इन्हें विकसित करने के क्रम में 20 नए एयरपोर्ट को बौद्ध सर्किट के शहरों से जोड़ा जाएगा। बजट में निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में मेडिकल पर्यटन और ह्यहील इन इंडिया' को भी बढ़ावा दिया जाएगा। हर साल जापान, वियतनाम, थाईलैंड,श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलयेशिया, लाओस, सिंगापुर आदि बौद्ध धर्म मानने वाले देशों से पर्यटक बड़ी संख्या में बौद्ध सर्किट की यात्रा करते हैं। इस क्रम में ई-वीजा की प्रक्रिया को और भी सरल बनाया जाएगा। अब तक 169 देशों के लिए ई वीजा की सुविधा देश में शुरू हो चुकी है।

बीरेन ने क्यों दिया इस्तीफा

भाजपा शासित इस राज्य में 3 मई 2023 से मैतेयी व कुकी समुदायों के बीच छिड़े जातीय हिंसक संघर्ष में जिस स्तर की हिंसा व अशांति देखनी पड़ी उसकी दूसरी मिसाल देश में कहीं भी देखने को नहीं मिलती। हिंसा, आगजनी, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार यहाँ तक कि हिंसक भीड़ द्वारा युवतियों की नग्न परेड कराने जैसी शर्मनाक घटनाएं घटीं। मंत्रियों,विधायकों व अन्य नेताओं के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस थाने आग की भेंट चढ़े,यहाँ तक कि शस्त्रागार के हथियार तक उपद्रवी छीन ले गये। सैकड़ों लोग इस संघर्ष में मारे गये जबकि हजारों लोग विस्थापित भी हुये। परन्तु मणिपुर का डबल इंजन मूक दर्शक बना रहा। कानून व्यवस्था की यह स्थिति राज्य में उस समय पैदा हुई थी जबकि मणिपुर की 60 सदस्यीय विधानसभा में एन डी ए के पास 52 सीटें हैं जिसमें अकेली भाजपा के पास 37 सीटें हैं। राज्य सरकार के लिये इससे बेहतर बहुमत और क्या हो सकता था?

भाजपा शासित इस राज्य में 3 मई 2023 से मैतेयी व कुकी समुदायों के बीच छिड़े जातीय हिंसक संघर्ष में जिस स्तर की हिंसा व अशांति देखनी पड़ी उसकी दूसरी मिसाल देश में कहीं भी देखने को नहीं मिलती। हिंसा, आगजनी, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार यहाँ तक कि हिंसक भीड़ द्वारा युवतियों की नग्न परेड कराने जैसी शर्मनाक घटनाएं घटीं। मंत्रियों,विधायकों व अन्य नेताओं के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस थाने आग की भेंट चढ़े,यहाँ तक कि शस्त्रागार के हथियार तक उपद्रवी छीन ले गये। सैकड़ों लोग इस संघर्ष में मारे गये जबकि हजारों लोग विस्थापित भी हुये। परन्तु मणिपुर का डबल इंजन मूक दर्शक बना रहा। कानून व्यवस्था की यह स्थिति राज्य में उस समय पैदा हुई थी जबकि मणिपुर की 60 सदस्यीय विधानसभा में एन डी ए के पास 52 सीटें हैं जिसमें अकेली भाजपा के पास 37 सीटें हैं। राज्य सरकार के लिये इससे बेहतर बहुमत और क्या हो सकता था?

बहरहाल मई 2023 से लेकर अभी तक जारी हिंसा के बीच लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गाँधी जहां तीन बार मणिपुर का दौरा कर हिंसा पीड़ितों के बीच जाकर वहां के लोगों से मिलकर हालात का जायजा ले चुके हैं वहीँ प्रधानमंत्री ने अभी तक एक बार भी हिंसाग्रस्त मणिपुर का दौरा करना मुनासिब नहीं समझा। हद तो यह है कि राहुल गाँधी व विपक्ष के तमाम प्रयासों के बावजूद सदन में मणिपुर पर चर्चा को भी टालने की कोशिशें हुईं। सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा मणिपुर की शर्मनाक घटनाओं को कांग्रेस शासित राज्यों से जोड़कर मणिपुर घटनाओं पर लीपापोती करने की कोशिश की गयी। निःसंदेह राहुल गाँधी देश के अकेले ऐसे नेता हैं जो लगातार मणिपुर हिंसा के विषय को उठाते रहे हैं । और भाजपा पर यह दबाव इतना बढ़ा कि मणिपुर विधानसभा में मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आने से पहले ही पार्टी ने आखिरकार उनसे त्याग पत्र ले ही लिया।

बीरेन सिंह के त्यागपत्र के बाद मणिपुर में भाजपा के लिये राजनैतिक संकट खड़ा होना तो निश्चित है ही साथ ही अब यह भी प्रमाणित हो चुका है कि बीरेन सिंह पूरी तरह से मणिपुर हिंसा को नियंत्रित कर पाने में असफल रहे हैं। अन्यथा क्या कारण था कि 3 मई 2023 से लेकर अब तक हिंसा पर पूर्ण नियंत्रण हासिल नहीं किया जा सका ? इसी दीर्घकालिक हिंसा के कारण भाजपा के ही अधिकांश विधायक बीरेन नेतृत्व के विरुद्ध होते जा रहे थे। और मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी भाजपा विधायकों द्वारा ही की जा रही थी। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना थी कि कहीं मणिपुर बीजेपी के हाथ से निकल न जाये। क्योंकि राज्य में हिंसा की भेंट चढ़े लंबा समय बीत चुका है और समाधान के नाम पर कुछ भी सामने नजर नहीं आ रहा। ऐसे में प्रदेश बीजेपी के अंदर ही काफी मतभेद शुरू हो गए थे.ह्वबीजेपी के लोग ही मुख्यमंत्री बदलने की मांग कर रहे थे। आगामी 10 फरवरी से विधानसभा सत्र शुरू होते ही मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। इसीलिये भाजपा नेतृत्व द्वारा दिल्ली चुनाव परिणाम के जश्न के बीच ही बीरेन सिंह से त्यागपत्र लेने का फैसला किया गया।

देखना होगा कि बंगाल सहित अन्य गैर भाजपा शासित राज्यों को जंगल राज व आपदा ग्रस्त सरकार बताने वाली भाजपा, मणिपुर में महा आपदा के रूप में विराजमान रहे मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को हटाने के बाद जातीय हिंसा में सुलगते मणिपुर के लोगों को भयमुक्त करने व उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाने के लिये क्या कदम उठती है। और देश की इस बात पर भी नजर रहेगी कि मणिपुर में डबल इंजन की सरकार के बुरी तरह से फेल होने का प्रभाव भविष्य में पूर्वोत्तर की भाजपा की राजनीति पर क्या पड़ेगा।

8 फरवरी को जब दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित हो रहे थे और भाजपा के साथ ही देश का मीडिया भी भाजपा की जीत के कसीदे बांचने में लगा था। देश को यह बताया जा रहा था कि दिल्ली से ह्यआपह्ल दा जा चुकी है। ठीक उसी समय भाजपा हाईकमान द्वारा निर्देशित भाजपा की मणिपुर की सबसे आपदा ग्रस्त डबल इंजन सरकार के मुख्यमंत्री नोंगथोम्बम बीरेन सिंह को त्यागपत्र देने हेतु निर्देशित किया जा चुका था जिसे दिल्ली जीत के जश्न से ठीक अगले दिन यानी 9 फरवरी को अमल में लाया गया। पिछले छह महीनों से मैतेई, कुकी और नागा विधायक एक साथ मिलकर मुख्यमंत्री बीरेन को पद से हटाने के लिए केंद्रीय नेताओं से बात कर रहे थे। खबरों के अनुसार गत 3 फरवरी को ही मणिपुर के 33 विधायकों ने, जिनमें 19 विधायक भाजपा के भी बताये जा रहे हैं,दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री व गृह मंत्री से मिलकर मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की जानकारी दे दी थी। बल्कि यह भी बता दिया था कि मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के विरुद्ध अविश्वास प्रस्तव आने की स्थिति में भाजपा विधायक भी अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। इसीलिये भाजपा नेतृत्व को भारतीय राजनीति के इतिहास के सबसे अकुशल,असफल व अकर्मण्य व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद से हटाना पड़ा। हाँ मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के त्याग पात्र के बावजूद यह सवाल हमेशा बना रहेगा कि इतनी व्यापक व दीर्घकालिक अनियंत्रित हिंसा होने के बावजूद आखिर भाजपा नेतृत्व ने किन परिस्थितियों में उन्हें मुख्यमंत्री पद से पहले क्यों नहीं हटाया ? इतना ही नहीं बल्कि बीरेन सिंह पर जातीय हिंसा के दौरान पक्षपात करने का भी आरोप है। बीरेन सिंह स्वयं मैतेई समुदाय से आते हैं। कुकी जनजाति के एक व्यक्ति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर यह आरोप लगाया गया था कि मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने राज्य में हिंसा भड़काई है। याचिकाकर्ता ने इससे सम्बंधित एक ऑडियो टेप भी अदालत में सबूत के तौर पर जमा कराया है। प्रयोगशाला ट्रुथ लैब्स ने इस बात की पुष्टि भी की है कि इस ऑडियो टेप में 93 प्रतिशत आवाज बीरेन सिंह की आवाज से मेल खाती है। गोया बीरेन सिंह राजधर्म का पालन न करने के भी खुले दोषी हैं।

एआई में दुनिया को बदलने की ताकत

भारत एआई की चुनौतियों एवं खतरों को लेकर सतर्क है। क्योंकि एआई द्वारा प्रस्तुत चुनौतियाँ बहुआयामी हैं और लगातार विकसित हो रही हैं। उदाहरण के लिए डीपफेक, जो डिजिटल मीडिया हैं-वीडियो, ऑडियो और चित्र-जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके संपादित और हेरफेर किया जाता है, हाइपर-रियलिस्टिक डिजिटल मिथ्याकरण को शामिल करते हैं। इसका संभावित रूप से प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने, सबूत गढ़ने और लोकतांत्रिक संस्थानों में विश्वास को कम करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। जबकि डीपफेक का इस्तेमाल चुनावों जैसे कुछ मामलों में किया गया है, उनका उपयोग विभिन्न अन्य क्षेत्रों में भी तेजी से देखा जा रहा है। डीपफेक के अलावा, एआई से जुड़े अन्य जोखिम भी हैं। इनमें गोपनीयता, पूर्वाग्रह, पारदर्शिता, जवाबदेही और दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए एआई के संभावित दुरुपयोग से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। भारत सरकार इन मुद्दों को सलाह और विनियमों के माध्यम से नियोजित एवं नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है जो पारदर्शिता, सामग्री मॉडरेशन, सहमति तंत्र और डीपफेक पहचान पर जोर देते हैं ताकि जिम्मेदार एआई तैनाती सुनिश्चित हो और चुनावी अखंडता की रक्षा हो सके। यह एक सतत प्रयास है और जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे, इन चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक मजबूत तंत्र के विकास के साथ सक्षम होने की अपेक्षा रहेगी। एआई विकसित होता रहेगा, नये-नये करिश्माई एवं चमत्कारी आयाम उससे जुड़ते रहेंगे और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह ऐसे तरीके से हो जो सभी के लिए सुरक्षित, नैतिक और लाभकारी हो। आवश्यक बुनियादी ढांचे, हार्डवेयर और क्लाउड कंप्यूटिंग क्षमताओं के विकास में सहायता के लिए निवेश महत्वपूर्ण है। सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग से आवश्यक पूंजी जुटाई जा सकती है। यह संयुक्त प्रयास एआई नवाचार, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा दे सकेगा और जिससे भारत एआई क्रांति में अग्रणी बन दुनिया का नेतृत्व कर सकेगा।

पेरिस में हुए दो दिवसीय एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) एक्शन समिट ने जहां दुनिया के लिए आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के महत्व को उजागर किया, वहीं यह भी साफ कर दिया कि इस मामले में होड़ के बावजूद सभी देशों का आपसी तालमेल बनाए रखते हुए सावधानी से आगे बढ़ना जरूरी है। एआई से बदलती दुनिया के चमत्कार वरदान से कम नहीं है, लेकिन इससे जुड़ी चुनौतियां एवं खतरे इसे अभिशाप में भी बदल सकते हैं। बहुत आवश्यक है कि इसके उपयोग के संदर्भ में कोई वैश्विक ढांचा एवं नियंत्रण का केन्द्र एवं नीति बने। क्योंकि एआई के दुरुपयोग के खतरे किसी से छिपे नहीं। अभी एआई का उपयोग अपने प्रारंभिक चरण में ही है, लेकिन उससे पैदा होने वाली कई चुनौतियों एवं खतरों ने सिर उठा लिया है। लेकिन इस नई तकनीक से जीवनशैली, शिक्षा, चिकित्सा, युद्ध, सेना, शासन-प्रशासन, चुनाव, व्यापार, विचार आदि में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। भारत एआई को लेकर बहुत उत्साहित है और दुनिया में एआई का सबसे बड़ा केन्द्र बनने को भी तैयार है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर बैठक की सह-अध्यक्षता की बल्कि अगली शिखर बैठक की मेजबानी करने की पेशकश भी करते हुए बता दिया कि भारत इस पहल को कितनी गंभीरता से लेता है।

भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर होते हुए तकनीकी विकास की दृष्टि से भी सफलता के नये झंडे गाड रहा है। एआई को लेकर भारत की सोच सकारात्मक एवं विकासमूलक है इसीलिये प्रधानमंत्री मोदी ने यह सही कहा कि इस तकनीक में दुनिया को बदलने की ताकत है, लेकिन अमेरिका की कुछ बड़ी तकनीकी कंपनियों ने सूचना संसार में अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया है। उनके एकाधिकार और उनकी मनमानी से निपटना विश्व के तमाम देशों के लिए मुश्किल हो रहा है। यदि इसी तरह का एकाधिकार एआई कंपनियों ने भी स्थापित कर लिया तो फिर समस्या गंभीर हो जाएगी।

सबसे अधिक समस्या विकासशील और निर्धन देशों को होगी, जो पहले से ही चुनिंदा तकनीकी कंपनियों के वर्चस्व तले दबी हुई है। मोदी ने एआई तकनीक के संतुलित एवं विवेकसम्मत उपयोग एवं विकास की आवश्यकता को भी व्यक्त किया। क्योंकि यह उन्नत तकनीक बनाने वाली कुछ कंपनियां उसे अपने हिसाब से संचालित करती हुई भी दिख रही हैं। इस तकनीक का मनमाना इस्तेमाल न होने पाए, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को प्रभावी कदम उठाने होंगे। यह एआई एक्शन समिट ऐसे समय हो रही है, जब चीनी कंपनी डीपसीक दुनिया को एक जबर्दस्त झटका दे चुकी है।

इसी पहलू को रेखांकित करती है यह पेरिस की तीसरी एआई एक्शन समिट, जिसमें दुनिया भर के 90 देशों और तमाम बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस हमारे भविष्य का अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन किसी भी वजह से इसकी ग्रोथ को बेकाबू होने दिया गया तो उसके परिणाम खतरनाक साबित हो सकते हैं। भारत की भूमिका को खास बनाता है इसका असाधारण टैलंट पूल, इसके वे इंजिनियर और वैज्ञानिक जो नाम मात्र की लागत पर बड़े-बड़े अंतरिक्ष अभियान को अंजाम देते रहे हैं। हालांकि अभी तक इस मामले में भारत की पहल बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। बेहतर होगा कि केंद्र सरकार एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाकर इस तकनीक को लेकर अपनी प्राथमिकता तय करे। इनोवेशन में भारत को हर जोखिम को उठाने के लिये स्वयं को सक्षम करना होगा। एआई का समुचित लाभ उठाने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। एआई के जरिये वे अनेक काम किए जा सकते हैं, जो अब तक मनुष्य करते रहे हैं, लेकिन यह ध्यान रहे कि उसमें मानवीय संवेदनाएं नहीं होतीं और वह उपलब्ध डाटा के आधार पर ही किसी नतीजे पर पहुंचती है। अब यदि डाटा ही सटीक न हो तो नतीजे भी नुकसान पैदा करने वाले हो सकते हैं। इस पर हैरानी नहीं कि अति उन्नत एआई को मानव सभ्यता के लिए संकट के रूप में भी देखा जा रहा है। इस आशंका को निर्मूल साबित करने वाले उपाय करना समय की मांग हैं और उन पर ज्यादा फोकस करना होगा।

इस तरह की तकनीक तभी लाभकारी सिद्ध होती है, जब उसका उपयोग समझदारी, नैतिकता एवं विवेकपूर्ण होता है। ज्यादा जरूरी है उसके दुरुपयोग की आशंकाओं पर प्रभावी ढंग से लगाम लगाने की स्थितियों एवं तंत्र को विकसित करने की। एआई के मामले में ऐसा इसलिए अनिवार्य रूप से करना होगा, क्योंकि यह मानव जीवन को कहीं गहराई से प्रभावित करने की क्षमता रखती है। एआई एक नई तकनीक है और बहुत से लोग उसके प्रयोग के तौर-तरीकों से अपरिचित हैं। इसीलिए यह आशंका उभरी है कि उस-के कारण रोजगार का संकट पैदा हो सकता है। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नौकरियों पर एआई के प्रभाव को समझने के लिए एक व्यापक, डेटा-समर्थित अध्ययन आवश्यक है। आईएमएफ की एक रिपोर्ट ने अनुमान लगाया है कि एआई दुनिया भर में लगभग 40 प्रतिशत नौकरियों को प्रभावित करेगा, कुछ को प्रतिस्थापित करेगा और दूसरों को पूरक करेगा। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एआई अपने उपयोग के विकास के साथ नए प्रकार की नौकरियां भी पैदा करेगा। एआई पहले से ही विनिर्माण से लेकर बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा, कृषि और शिक्षा तक सभी क्षेत्रों में बदलाव ला रहा है। उदाहरण के लिए, शिक्षा क्षेत्र में, एआई व्यक्तिगत पाठ्यक्रम, परीक्षण, सीखने के तरीके और वितरण को सक्षम करके भारत के सीखने के परिदृश्य को बदल रहा है। निःसंदेह यह नई तकनीक अवसर बन रही है, तकनीकी विकास का सूरज बनकर नयी समाज संरचना को बल दे रही है। यह संभावनाभरा है कि पेरिस शिखर सम्मेलन में एआई के क्षेत्र में भारत और प्रमुख देशों के बीच सामंजस्य बढ़ने के संकेत मिले, लेकिन बात तब बनेगी, जब यह मंच एआई के नियमन एवं नियोजित विकास के लिए सहमति कायम करने की बुनियाद बने। एआई की तीव्र प्रगति और व्यापक अनुप्रयोग को देखते हुए, भारत के लिए अपना स्वयं का एआई सुरक्षा संस्थान स्थापित करना अपेक्षित है। ऐसा संस्थान सुरक्षित और नैतिक एआई प्रथाओं को विकसित करने, अनुसंधान करने और एआई के उपयोग में सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।

डंकी रूट से अमेरिका जाना अवैध

अवैध रूप से अमेरिका जाने का जो तरीका सबसे अधिक चर्चा में है, उसे डंकी रूट कहा जाता है। इस रूट के जरिए अमेरिका पहुंचने की कोशिश करने वालों को जोखिमों का सामना करना पड़ता है-जान का खतरा, लूट-खसोट, यौन शोषण, गिरोहों द्वारा बंधक बनाए जाने जैसी घटनाएं आम हैं। सच्चाई यह है कि यह स्वर्गिक आनंद उठाने का नारकीय मार्ग है। जो व्यक्ति डंकी रू ट से अमेरिका जाने की योजना बनाता है, उसे औसतन 40 से 50 लाख रु पये खर्च करने पड़ते हैं। यह पैसा एजेंटों, फर्जी दस्तावेज, यात्रा और अन्य व्यवस्थाओं में लग जाता है। लेकिन इस मोटी रकम के बावजूद कोई गारंटी नहीं कि व्यक्ति सुरक्षित अमेरिका पहुंच ही जाएगा। अमेरिका तक पहुंचने के लिए कई देशों से होते हुए बेहद खतरनाक सफर तय करना पड़ता है। इसमें आम तौर पर दुबई, रूस, यूरोप, दक्षिण अमेरिका और फिर मैक्सिको जैसे देशों का रास्ता लिया जाता है। मैक्सिको से अमेरिका की सीमा पार करना सबसे खतरनाक पड़ाव होता है। यहां कई बार लोगों को मानव तस्कर गिरोहों के हाथों लूट लिया जाता है, महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं आम हैं, और कई बार लोगों को बंदी बना कर फिरौती मांगी जाती है। यह यात्रा इतनी कठिन होती है कि कई लोग इसे पूरा करने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर रेगिस्तान और जंगलों में हर साल सैकड़ों शव पाए जाते हैं, जो इस खतरनाक

सफर की भयावहता दशार्ते हैं। अगर कोई खतरनाक सफर के बाद अमेरिका पहुंच भी जाता है, तो भी मुश्किलें खत्म नहीं होतीं। उसे या तो राजनीतिक शरण का दावा करना पड़ता है या कोई और बहाना बनाना पड़ता है ताकि अमेरिका में रह सके। राजनीतिक शरण पाने के लिए लोग अक्सर झूठे दावे करते हैं। कई लोग भारत में राजनीतिक उत्पीड़न का झूठा दावा करते हैं-कहते हैं कि उनकी जान को खतरा है, उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, या भारत में उन्हें धार्मिक या जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। कुछ तो यहां तक कह देते हैं कि उनके अपने माता-पिता ही उनके दुश्मन हैं ताकि वे अमेरिका में अपने ठहरने के लिए कोई ठोस आधार बना सकें। हालांकि, अमेरिका की नई आव्रजन नीति अब ऐसे झूठे दावों को परखने के लिए और अधिक सख्त हो चुकी है। किसी का दावा गलत पाया जाता है, तो उसे न सिर्फ डिपोर्ट कर दिया जाता है, बल्कि आजीवन अमेरिका में प्रवेश की अनुमति भी नहीं मिलती।

भारत में, खासकर पंजाब, गुजरात और हरियाणा में, हजारों एजेंट सक्रिय हैं, जो लोगों को अमेरिका, कनाडा और यूरोप भेजने का झांसा देते हैं। ये एजेंट लोगों से 30-50 लाख रु पये तक वसूलते हैं, और उन्हें यकीन दिलाते हैं कि वे किसी न किसी तरह अमेरिका पहुंच ही जाएंगे। लेकिन वे किसी की सुरक्षा या कानूनी स्थिति की गारंटी नहीं देते। जब लोग किसी मुसीबत में फंसते हैं, तो एजेंट उनसे कोई संपर्क नहीं रखते और कई बार फरार हो जाते हैं। जो लोग डंकी रूट से अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं, वे अपनी ही नहीं, बल्कि अपने परिवार की जिंदगी भी दांव पर लगा देते हैं। जब डिपोर्ट हो जाते हैं, तो उनका परिवार आर्थिक संकट में आ जाता है। घर-जमीन तक बिक जाते हैं, कर्ज का बोझ बढ़ जाता है, और समाज में बदनामी का डर अलग से रहता है। डंकी रूट पर गए कई लोग रास्ते में लापता भी हो जाते हैं, या मारे जाते हैं। उनके परिवार वर्षों तक नहीं जान पाते कि उनके बेटे या भाइयों का क्या हुआ।

अवैध आप्रवासन की समस्या से निपटने के लिए जरूरी है कि लोगों को इसके खतरों के बारे में जागरूक किया जाए। सरकार को भी चाहिए कि ऐसे एजेंटों पर कड़ी कार्रवाई करे और युवाओं के लिए देश में ही रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करे। युवाओं को भी समझना होगा कि विदेश जाकर पैसा कमाना आसान रास्ता नहीं है। अगर वे कानूनी तरीके से विदेश जाना चाहते हैं, तो उन्हें सही प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। अवैध आप्रवासन को उचित नहीं ठहराया जा सकता। अवैध आप्रवासन का अंत दुखद ही होता है। यह सपना भले ही सुनहरा दिखे, लेकिन इसकी असलियत बेहद भयावह होती है। भारत के युवाओं को सोचना होगा कि क्या वे वाकई अपनी जिंदगी को इस तरह के जोखिम में डालना चाहते हैं? या फिर वे कानूनी और सुरक्षित रास्तों को अपना कर अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहेंगे? फैसला उनके हाथ में है।

घूँघट की बगावत

16 फरवरी 2025

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

6

विदेशी सहायता देने वालों के होते अपने संकीर्ण स्वार्थ

यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यूएसएड का उस फ्रीडम हाउस नामक संस्था से गठजोड़ है, जो भारतीय लोकतंत्र को लगातार निचले पायदान पर रखती है और यह संदेश देने की कोशिश करती है कि भारत में लोकतंत्र कमजोर होता जा रहा है। इन सनसनीखेज दावों के बीच विकिलीक्स ने भी उजागर किया है कि यूएसएड ने स्वतंत्र पत्रकारिता के विकास का दावा करने वाली इंटरन्यूज नामक एक अन्य संस्था को लगभग 4,100 करोड़ का अनुदान दिया। इस अनुदान का एक हिस्सा भारत भी आया, जिसमें बड़ी रकम सुप्रीम कोर्ट के एक वकील की ऐसी संस्था को मिली, जिसके परामर्शदाता और उसके द्वारा संचालित कार्यशालाओं में मोदी विरोधी एक्टिविस्ट और पत्रकारों के नाम सामने आते हैं। ये सभी मोदी सरकार के धुर विरोधियों में गिने जाते हैं। इनमें से कई की गिनती वामपंथियों में भी होती है। यह भी कोई संयोग नहीं कि अमेरिकी दूतावास ने 1.6 करोड़ के बजट की घोषणा से पब्लिक मीडिया ट्रेनरों की नियुक्ति के लिए जो मुहिम चलाई थी, उसके नेतृत्व के लिए इन्हीं के बीच के एक यूट्यूबर पत्रकार को चुना था और उसे दूतावास निमंत्रित किया था। द पैंफलेट नामक पोर्टल ने कुछ समय पहले यह उजागर किया था कि अंधविरोध से ग्रस्त घोर मोदी विरोधी और मैग्सेसे पुरस्कार विजेता एक भारतीय पत्रकार पर अमेरिका में बनाई गई डाक्युमेंट्री को फोर्ड फाउंडेशन से आर्थिक सहायता मिली थी। इससे पहले राजीव गांधी फाउंडेशन को जार्ज सोरोस से अनुदान मिलने की खबर आई थी, परंतु अब सैम पित्रोदा के एनजीओ जीकेआइ को भी यूएसएड से पैसा मिलने की बात सामने आई है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जबसे अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य अमेरिकी एजेंसी अर्थात यूएसएड का अमेरिकी विदेश विभाग में विलय करने का निर्णय लिया है, तबसे इस एजेंसी के कार्यकलापों को लेकर चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन हो रहे हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे कुछ अच्छे प्रयासों पर धन खर्च करने वाली यह संस्था अमेरिका के सत्ता परिवर्तन अभियान का जरिया भी बनी हुई थी।

अमेरिकी विदेश विभाग के पूर्व अधिकारी माइक बेंज ने दावा किया है कि यूएसएड ने विभिन्न माध्यमों से बांग्लादेश में तख्तापलट को प्रोत्साहित करने के बाद भारतीय विमर्श को भी प्रभावित करने का प्रयास किया। बेंज के अनुसार अमेरिका ने बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार को कमजोर करने के लिए सांस्कृतिक तनाव का इस्तेमाल कर उनकी सरकार के खिलाफ भावनाओं को भड़काया।

बेंज ने आरोप लगाया है कि यूएसएड अन्य अमेरिकी सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर भारत में मोदी विरोधी राजनीतिक कथानक को तैयार करने के लिए लगातार प्रयास करती रही है। इस कथानक का उपयोग 2019 के आम चुनावों में मोदी विरोधी हवा बनाने के लिए तो किया ही गया, साथ ही आनलाइन विमर्श में हेराफेरी करने, विपक्षी आंदोलनों को वित्तपोषित करने और कुछ दृष्टिकोणों को सेंसर करने के लिए भी किया गया।

बेंज की मानें तो यूएसएड और उसके सहयोगियों ने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा को गलत सूचनाएं यानी फेक न्यूज प्रचारित करने का आरोपित बनाकर पेश किया और ऐसा चित्रण तैयार करने के बाद फेसबुक, वाट्सएप, यूट्यूब और ट्विटर (एक्स) जैसे इंटरनेट मीडिया नेटवर्क पर मोदी समर्थक सामग्री को सरंशिप के दायरे में लाने का औचित्य गढ़ा। बेंज का दावा है कि यूएसएड से जुड़े संगठनों ने भारत में फेक न्यूज की फर्जी रिपोर्ट तैयार करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मीडिया और डिजिटल फोरेंसिक समूहों के साथ सहयोग भी किया।

यह ध्यान रहे कि राहुल गांधी के अमेरिकी कार्यक्रमों को आयोजित करने का कार्यभार सैम पित्रोदा के जिम्मे ही रहता है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि गांधी परिवार के राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से चंदा मिला था।

इसके चलते फाउंडेशन का विदेश चंदे संबंधी एफसीआरए लाइसेंस को रद कर दिया गया था। भारतीय राजनीति और भारतीय मीडिया में विदेशी दखल का चलन नई बात नहीं है। मित्रोखिन आर्काइव्स में वर्णित सोवियत रूसी हस्तक्षेप से लेकर चीनी फंडिंग प्राप्त एक न्यूज पोर्टल की ओर से देश में अराजकता फैलाने के प्रकरण समय-समय पर उजागर होते रहे हैं। देश की राजनीति में विदेशी और खासकर अमेरिकी हस्तक्षेप और राजनीतिक एवं मीडिया कथानक को पैसे के दम पर तोड़ने-मरोड़ने का प्रयास इस मायने में भिन्न है कि यह बेशर्मी से खुलेआम हो रहा है।

यूएसएड के जरिये अमेरिकी प्रयास इस मायने में और भी खतरनाक थे कि वे राजनीति के अलावा लोकतंत्र के विभिन्न अंगों को प्रभावित और अधिग्रहित कर भारतीय संप्रभुता को खुली चुनौती दे रहे थे। इसके अलावा ऐसे प्रयास दूरगामी सामाजिक एवं सांस्कृतिक विप्लव की जमीन भी तैयार करते हैं। यूएसएड द्वारा मोटा चंदा प्राप्त वर्ल्ड विजन और परोक्ष रूप से सहायता प्राप्त जोशुआ प्रोजेक्ट इसका उदाहरण हैं। ये संस्थाएं न सिर्फ मतांतरण करा रही हैं, बल्कि हिंदुओं के प्रति घृणा का माहौल भी तैयार करती हैं।

चाहे राजनीति हो या पत्रकारिता, एक्टिविज्म हो या फिर सामाजिक कार्य, भारत में सभी प्रकार के लोगों को अपनी रुचि और अपने मंतव्य के अनुसार चलने की पूरी छूट है, परंतु एक संप्रभु राष्ट्र का स्वाभिमान इसकी अनुमति कभी नहीं दे सकता कि विदेशी ताकतों और विदेशी पैसे के बल पर देश की दशा-दिशा प्रभावित हो। यह बहुत चिंताजनक बात है कि न सिर्फ पत्रकार और एक्टिविस्ट किस्म के लोग, बल्कि कुछ राजनेता भी अमेरिकी हाथों में खेलने को तैयार हैं।

ऐसी दुष्चेष्टा की जितनी निंदा की जाए, कम है। इसके प्रति देश को सावधान रहना होगा। इसके साथ ही सरकार को भी चाहिए कि विदेशी फंडिंग के जटिल से जटिल मार्गों को रोकने का प्रबंध करे। अमेरिका में बदले राजनीतिक परिदृश्य और डोनाल्ड ट्रंप की साफगोई वाली विदेश नीति इसमें तात्कालिक रूप से सहायक सिद्ध हो सकती है, लेकिन भारत को अपने हितों की रक्षा के लिए और अधिक सक्रिय होना होगा। इसलिए और भी, क्योंकि आम तौर पर विदेशी सहायता देने वालों के अपने संकीर्ण स्वार्थ होते हैं।

देश व समाज के लिए अनुपयोगी बन रहे मुफ्तखोर

जो दल सरकार में होता है वह योजनाएं घोषित करने और उसे लागू करने में सक्षम होता है क्योंकि उसके पास राजकोष का धन होता है और भविष्य की राजनीति करने के लिए लोगों को लुभाने की स्थितियां भी होती है। लेकिन जो सत्ता से बाहर होते हैं ऐसे राजनीतिक दल सत्तारूढ़ दलों से दो कदम और भी आगे जाकर मुफ्त की घोषणाएं करते हैं जिससे वे सत्ता में आ सके इसलिए इस प्रकार की होड़ सत्तारूढ़ और विपक्ष के राजनीतिक दलों में इतनी बढ़ गई है कि सुप्रीम कोर्ट को भी इसका संज्ञान लेना पड़ा है।

सरकार को चाहिए कि वह काम के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करे और हर हाथ को उसकी योग्यता क्षमता के अनुरूप कार्य दे और उसका मेहनताना दे न कि मुफ्तखोरी कराकर उसे देश और समाज के लिए अनुपयोगी बना दे कि वह सरकार की ओर देखता रहे कि कब वह रोटी का टुकड़ा डाले। सरकार को ऐसा माहौल बनाना होगा जिसमें व्यक्ति स्वयं आत्मनिर्भर बनें और स्वाभिमान और सम्मान के साथ अपना जीविकोपार्जन कर सके। किसी भी देश या समाज का विकास इसी आधार पर हो सकता है नहीं तो सरकार के चंद टुकड़ों पर आश्रित समाज परजीवी ही बन जायेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा पहली बार नहीं कहा है। इसके पहले भी वह फ्रीबीज को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांग चुकी है और अपनी अप्रसन्नता भी प्रकट कर चुकी है। सवाल यह है कि वही घोषणा कैसे एक राजनीतिक दल के लिए गरीब कल्याण हो जाती है और दूसरे के लिए मुफ्त रेवड़ी ? एक राजनीतिक दल यदि दूसरी पार्टी के इस तरह के वादे को रेवड़ियां बताता है तो वहीं वह अपने घोषणाओं को लोककल्याणकारी, गरीब कल्याण, लाडली बहना, लड़की बहिन योजना के नाम से देता और इनकी धनराशि को मतदान के दिन उनके खातों में स्थानान्तरित किया जाता है। जो एक तरह से चुनावी आचारसंहिता का उल्लंघन कहा जा सकता है लेकिन ऐसी स्कीमें चूंकि अधिसूचना जारी होने से पहले लागू कर दी जाती हैं इसलिए वे इस श्रेणी में नहीं आ पाती है।

जहां तक सुप्रीम कोर्ट का राजनीतिक दलों द्वारा किए गये मुफ्त रेवड़ियों के वादे का प्रश्न है, इसका प्रभाव कार्यसंस्कृति पर पड़ता है। इससे वह समाज न तो अपना विकास कर पाता है और न ही देश के विकास में ही उसका योगदान हो पाता है। उसकी स्थिति खेती के उस टुकड़े की भांति

सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव के मौके पर मुफ्त रेवड़ियों के वादे को लेकर टिप्पणी की है और नाराजगी भी जतायी है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठावा है कि चुनावों के दौरान मुफ्त की स्कीमों की घोषणा किए जाने के कारण लोग काम करने से बच रहे हैं और देश के विकास में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। जस्टिस बीआर गवई ने यहां तक कहा कि, 'दुर्भाग्य की बात है कि मुफ्त में मिलने वाली चीजों के कारण.... लोग काम करने से बचने लगे हैं। उन्हें मुफ्त में राशन मिल रहा है। उन्हें बिना कुछ काम किए ही पैसे मिल रहे हैं।' क्या हम इससे परजीवियों का एक वर्ग नहीं बना रहे है?

हो जाती है जिसके उत्पादन से उसका घर भी नहीं चल सकता है और न ही वह उस पर ठीक से खेती ही कर पाता है। सरकारें और राजनीतिक दल चंद टुकड़े और खाद्यान्न देकर या उसे देने का वादा करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेती हैं। समाज को मुख्यधारा में शामिल किया जा सके इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। गरीब लोगों को उचित दर पर राशन मिल सके इसके लिए उचित दरों के आवश्यक वस्तुओं की दूकानें खोली गई, जहां गरीब और जनसामान्य लोगों के लिए सस्ते दर पर आवश्यक वस्तुएं सुलभ करायी गई। राजशाही के दौर में जब अकाल होता था, संकट का समय होता था तब गोदाम खोले जाते थे लेकिन उनसे श्रम भी कराया जाता था। बहुत से महल और इमारते इन्हीं अकाल के दौर की देन हैं जो काम के बदले अन्न योजना जैसी व्यवस्था का हिस्सा था।

सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव के मौके पर मुफ्त रेवड़ियों के वादे को लेकर टिप्पणी की है और नाराजगी भी जतायी है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठावा है कि चुनावों के दौरान मुफ्त की स्कीमों की घोषणा किए जाने के कारण लोग काम करने से बच रहे हैं और देश के विकास में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। जस्टिस बीआर गवई ने यहां तक कहा कि, 'दुर्भाग्य की बात है कि मुफ्त में मिलने वाली चीजों के कारण.... लोग काम करने से बचने लगे हैं। उन्हें मुफ्त में राशन मिल रहा है। उन्हें बिना कुछ काम किए ही पैसे मिल रहे हैं।' क्या हम इससे परजीवियों का एक वर्ग नहीं बना रहे है?

एक तरफ जो पार्टियां सत्ता में है वे तरह-तरह के वादे कर रह हैं और चुनावी अधिसूचना जारी होने के चंद दिनों पहले नई-नई स्कीमें लांच करके मतदाताओं को रिझाने का काम करती हैं। जिससे लोग उनकी पार्टी को ही वोट दें। सत्तारूढ़ एक राजनीतिक दल ने तो बाकायदा ऐसे लाभार्थियों की लिस्ट तैयार करके उनका सम्मेलन करने और बूथ प्रबन्धन के जरिए इन लाभार्थियों के वोट डलवाने का काम कर रही हैं। 'आधार' ऐसे लोगों का डोजियर बन चुका है जब चाहें बैंकों और ऋणदाताओं की भांति ही उनका पूरा डाटा अपनी पार्टियों में संग्रहित रखती हैं। जिनका उपयोग चुनाव के दौरान वाररूम के माध्यम से किया जाता है। जनता से लिए गए टैक्स की वसूली करके इस प्रकार की लोक लुभावनी स्कीमें लायी जाती हैं। जिससे एक बड़े वर्ग को इस प्रकार से कवर किया जाता है मानों वह राजनीतिक दलों के जेब से दिया जा रहा हो। जबकि यह राजकोष का पैसा है जिसका इस्तेमाल लोगों को नकदी देकर और खाद्यान्न देकर किया जा रहा है। कविड के समय में जब लाकडाउन और पूरा बंदी की वजह से आवश्यक जरूरतों के तौर पर पका भोजन, सूखा राशन देने की जो शुरूआत की गई थी उसकी चुनावी सफलता को देखते हुए उसे पांच साल तक बढ़ा दिया गया जिसके दूरगामी प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। यहीं नहीं बड़ी संख्या में बेरोजगारों की फौज को देखते हुए आउट-सोर्सिंग और गैर सरकारी तौर पर अपने कार्यकताओं को विभिन्न 'मित्र' बनाकर चंद टुकड़े उनको भी डाल दिए जाते हैं। इससे वह आत्मनिर्भर होने के बजाव सरकार पर आश्रित हो जाता है क्योंकि उसकी न्यूनतम जरूरतें मुफ्त की इन रेवड़ियों से पूरी हो जाती है।

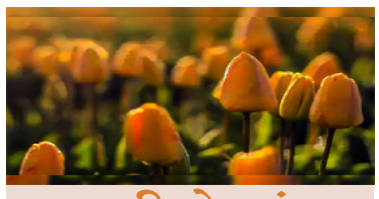

उम्मीदो संग बसंत आया है

अल्हड़पन से भरते जीवन में
खुमारी से सजे इस यौवन में
रंगों की नव सौगात लाया है
उम्मीदो संग बसंत आया है

जगत की अंधकार डगर में
रिश्तो की टूटे इस संसार में
उम्मीद की नई बाहर लाया है
उम्मीदो संग बसंत आया है

जगत के इस आपाधापी में
जीवन की भूल व माफी में
खुशियों की बारात लाया है
उम्मीदो संग बसंत आया है

मौरो की मोहक मादकता में
पलाश की रंगी मोहकता में
नव जीवन मे प्रभात लाया है
उम्मीदो संग बसंत आया है

चहक रहे पंछीयो के कलरव
बदल रही है प्रकृति नित नव
फिजा में ऋतू राज आया है
उम्मीदो संग बसंत आया है

तन मन प्रफुल्लित हो जाये
हर शैय मन को भी लुभाये
जग में नव खुमार छाया है
उम्मीदो संग बसंत आया है

प्रमेशदीप मानिकपुरी
आमाचानी धमतरी छ ग

भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त की हैं असाधारण उपलब्धियां

दिनांक 31 जनवरी 2025 को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को अपने सम्बोधन में, हाल ही के समय में, भारत में विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त की गई उपलब्धियों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा है कि ह्लभारत की विकास यात्रा के इस अमृतकाल को आज मेरी (केंद्र) सरकार अभूतपूर्व उपलब्धियों के माध्यम से नई ऊर्जा दे रही है। तीसरे कार्यकाल में तीन गुना तेज गति से काम हो रहा है। आज देश बड़े निर्णयों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है। और, इन निर्णयों में देश के गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाओं, किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली है ह्ल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिए गए उक्त भाषण में अंशों को जोड़कर इस लेख में यह बताने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार भारत में गरीब वर्ग, युवाओं, मातृशक्ति, किसानों, आदि के लिए विभिन्न योजनाएं सफलतापूर्वक चलाई जा रही हैं।

आज आम नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। समस्त परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए तीन करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 5 लाख 36 हजार करोड़ रुपए की राशि का खर्च किए जाने की योजना है। इसी प्रकार, गांव में गरीबों को उनकी आवासीय भूमि का हक देने के उद्देश्य से स्वामित्व योजना के अंतर्गत अभी तक 2 करोड़ 25 लाख सम्पत्ति कार्ड जारी किए जा चुके हैं। साथ ही, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लगभग 11 करोड़ किसानों को पिछले कुछ महीनों में 41,000 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। जनजातीय समाज के पांच करोड़ नागरिकों के लिए ह्लधरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्षह्व अभियान प्रारंभ हुआ है। इसके लिए अस्सी हजार करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। आज मध्यम वर्ग को मकान/फ्लैट खरीदने के लिए लोन पर सब्सिडी भी दी जा रही है एवं रेरा जैसा कानून बनाकर मध्यम वर्ग के स्वयं के मकान सम्बंधी सपने को सुरक्षा दी गई है।

देश के नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से आयुषमान भारत योजना चलाई जा रही है। अब इस योजना के अंतर्गत 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देने का निर्णय लिया गया है। इन वरिष्ठ नागरिकों को प्रत्येक वर्ष में पांच लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा आज युवाओं की शिक्षा और उनके लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा में वित्तीय सहायता देने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना शुरू की गई है। एक करोड़ युवाओं को शीर्ष पांच सौ कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर भी दिये जाएंगे। पेपर लीक की घटनाओं को रोकने और भर्ती में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नया कानून लागू किया गया है ।सहकार से समृद्धि की भावना पर चलते हुए सरकार ने ह्यत्रिभुवनह्ल सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।

जब देश के विकास का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी मिलने लगता है तभी विकास सार्थक होता है। गरीब को गरिमापूर्ण जीवन मिलने से उसमें जो सशक्तिकरण का भाव पैदा होता है, वो गरीबी से लड़ने में उसकी मदद करता है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत बने 12 करोड़ शौचालय, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निशुल्क दिए गए 10 करोड़ गैस कनेक्शन, 80 करोड़ जरूरतमंदों को राशन, सौभाग्य योजना, जल जीवन मिशन जैसी अनेक योजनाओं ने गरीब को ये भरोसा दिया है कि वो सम्मान के साथ जी सकते हैं। ऐसे ही प्रयासों की वजह से देश के 25 करोड़ लोग गरीबी को परास्त करके आज अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने नियो मिडिल क्लास का एक ऐसा समूह तैयार किया है, जो भारत की ग्रोथ को नई ऊर्जा से भर रहा है। उड़ान योजना ने लगभग डेढ़ करोड़ लोगों का हवाई जहाज में उड़ने का सपना पूरा किया है। जन औषधि केंद्र में 80 प्रतिशत रियायती दरों पर मिल रही दवाओं से, देशवासियों के 30 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा बचे हैं। हर विषय की पढ़ाई के लिए सीटों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी का बहुत लाभ मध्यम वर्ग को मिला है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में पच्चीस हजार बस्तियों को जोड़ने के लिए 70,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की हैं। आज जब हमारा देश अटल जी की जन्म शताब्दी का वर्ष मना रहा है, तब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उनके विजन का पर्याय बनी हुई है। देश में अब 71 वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेन चल रही हैं, जिनमें पिछले छह माह में ही 17 नई वंदे भारत और एक नमो भारत ट्रेन को जोड़ा गया है।

आगे आने वाले समय में देश के आर्थिक विकास में देश की आधी आबादी अर्थात मातृशक्ति के योगदान को बढ़ाना ही होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 91 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को सशक्त किया जा रहा है। देश की दस करोड़ से भी अधिक महिलाओं को इसके साथ जोड़ा गया है। इन्हें कुल नौ लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि बैंक लिंकेज के माध्यम से वितरित की गई है। केंद्र सरकार ने देश में तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने लक्ष्य निर्धारित किया है। आज एक करोड़ 15 लाख से भी अधिक लखपति दीदी एक गरिमामय जीवन जी रही हैं। इनमें से लगभग 50 लाख लखपति दीदी, बीते 6 महीने में बनी हैं। ये महिलाएं एक उद्यमी के रूप में अपने परिवार की आय में योगदान दे रही हैं। भारत में सभी के लिए बीमा की भावना के साथ कुछ महीने पूर्व ही बीमा सखी अभियान भी शुरू किया गया है। बैंकिंग और डिजी पेमेंट सखियां दूर दराज के इलाकों में लोगों को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। कृषि सखियां नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दे रही हैं और पशु सखियों के माध्यम से देश का पशुधन मजबूत हो रहा है। आज भारत में बड़ी संख्या में महिलाएं लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, पुलिस में भर्ती हो रही हैं और कॉरपोरेट कंपनियों का नेतृत्व भी कर रही हैं। आज बालिकाओं की भर्ती राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में भी प्रारंभ हो गई है। नेशनल डिफेंस अकैडमी में भी महिला कैडेट्स की भर्ती शुरू हो गई है। पिछले एक दशक में मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहल ने युवाओं को रोजगार के अनेक अवसर प्रदान किए हैं। पिछले दो वर्षों में सरकार ने, रिकॉर्ड संख्या में दस लाख स्थायी सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं। युवाओं के बेहतर कौशल और नए अवसरों के सृजन के लिए दो लाख करोड़ रुपए का पैकेज केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप की व्यवस्था से युवाओं को ग्राउंड पर काम करने का अनुभव प्राप्त होगा। आज भारत में डेढ़ लाख से अधिक स्टार्टअप हैं जो इनोवेशन के स्तंभ के रूप में उभर रहे हैं। एक हजार करोड़ रुपए की लागत से स्पेस सेक्टर में वेंचर कैपिटल फंड की शुरूआत भी की गई है। आज भारत क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। अर्थात, फ्यूचर ऑफ वर्क श्रेणी में अकऔर डिजिटल तकनीक अपनाने में भारत दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी भारत की रैंकिंग 76 से सुधर कर 39 हो गई है। यह सब भारतीय युवाओं के भरोसे ही सम्भव हो पा रहा है। देश में आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए आधुनिक शिक्षा व्यवस्था तैयार की जा रही है। कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे, इसीलिए मातृभाषा में शिक्षा के अवसर दिये जा रहे हैं। विभिन्न भर्ती परीक्षाएं तेरह भारतीय भाषाओं में आयोजित कर, भाषा संबंधी बाधाओं को भी दूर किया गया है। बच्चों में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए दस हजार से अधिक स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स खोली गई हैं। ह्लईज ऑफ डूइंग रिसर्चह्व के लिए हाल ही में वन नेशन-वन सब्सक्रिप्शन स्कीम लायी गई है। इससे अंतरराष्ट्रीय शोध की सामग्री निशुल्क उपलब्ध हो सकेगी।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक पंकज धर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस निकट रीड्स साहब का धर्मशाला से मुद्रित एवं 45, बादशाह बाग, जगन्नाथपुर, गोरखपुर से प्रकाशित।

संपादकः पंकज धर द्विवेदी

संपर्क सूत्र : ghoonghatkibagawat37@gmail.com